

मूल्य : 25 रुपये  
अक्टूबर - दिसम्बर, 2023

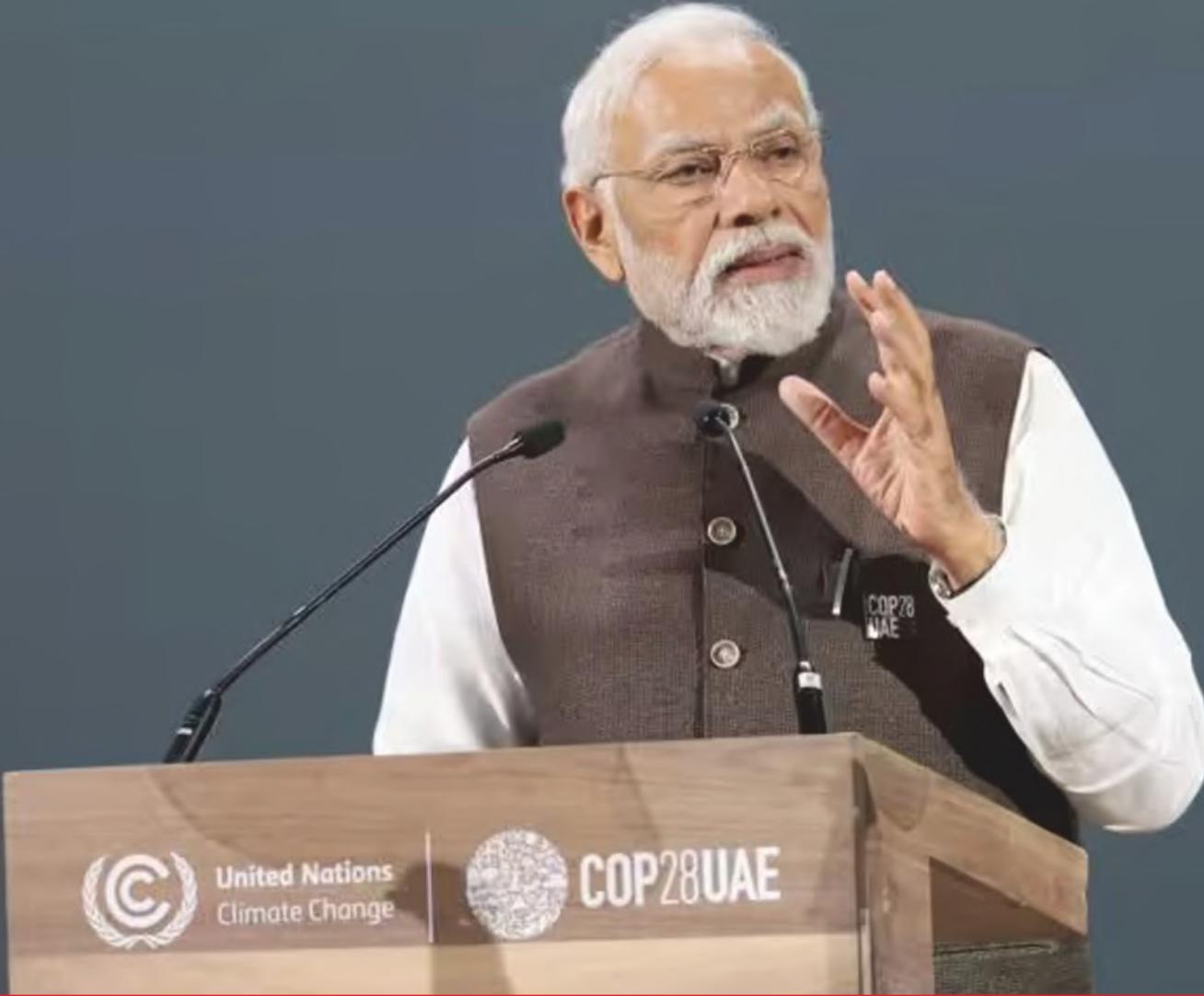


वर्ष : 13, अंक : 50

# नर्मदा समय

नदी के घर से नदी की बात...

एक पृथ्वी - एक परिवार - एक भविष्य





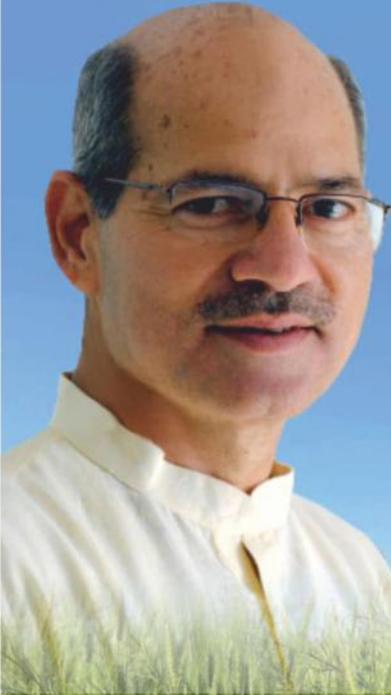
# प्राकृतिक जीवनशैली अपनाएं

**नर्मदा समग्र  
'प्रेरणा दिवस'**

**'विजयादशमी'**

**श्रद्धेय  
अनिल माधव दवे जयंती**

(तिथि अनुसार)



भारतीय जीवन और परिवेश उसकी कृषि परम्परा से विकसित हुआ है। कृषि करने के तरीके जीविकोपार्जन और विकास के लिए विकसित किये गये। हमारे पूर्वजों की प्राकृतिक जीवन शैली थी और उन्होंने समृद्ध विकसित संपदा हमें सौंपी। बदलते परिदृश्य और विकास की अतिमहत्वाकांक्षी अनावश्यक प्रतिस्पर्धा ने जीवन को अप्राकृतिक बना दिया। हमारी जीवन शैली, प्राकृतिक या अप्राकृतिक हो गयी। हमारे कार्य-व्यवहार में रसायन इतना रच-बस गया कि दैनिक जीवन में उपयोग से लेकर रसायनिक कृषि के माध्यम से मिट्टी तक समा गया। यही नहीं समूचे पर्यावरण में रासायनिक प्रदूषण आज विश्व चिंता का विषय है। रसायन से मुक्ति की कल्पना करना और इसे व्यवहार में लाना दो अलग बातें हैं। यह अप्राकृतिक और प्राकृतिक जीवन रचना के बीच संघर्ष है। मेरा स्पष्ट मत है कि युद्ध कभी एक मोर्चे पर नहीं जीता जाता। हमें इसके सभी पक्षों पर विजय प्राप्त करना होगा।

हमें रसायन मुक्त जीवनशैली की रचना करनी होगी। यह प्रयास निजि स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और दैनिक जीवन में करना होगा। धीरे-धीरे समाज में बदलाव लाना होगा। रसायन से मुक्ति के लिये मुक्त जीवनशैली की ओर जाना होगा। प्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक कृषि को लेकर नर्मदा समग्र के विचार का यही आधार है।

सबसे पहले हम निजी जीवन में उपयोग किये जाने वाले रसायन पदार्थों को अपने जीवन से बाहर निकालने का प्रयास करें। आरंभिक प्रयत्न से व्यक्ति रासायनिक पदार्थों का उपयोग बंद करें। जब व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज तक यह परिवर्तन की धारा बहेगी तभी रसायन मुक्त जीवन शैली की कल्पना सार्थक होगी। जीवन से और व्यवहार से रसायनों का निकालने के उपरांत ही रसायन मुक्त धरती, हवा, पानी की कल्पना की जा सकती है। अन्यथा विश्व में घुलनशील पदार्थ जो अलग-अलग तत्वों से घुले हुए हैं वे सब धरती पर आ जाएंगे और धरती को नष्ट कर देंगे। धरती बचाने, जल कण को शुद्ध रखने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में नर्मदा समग्र का यह विचार आरंभिक प्रयास है। अपेक्षा है कि यह समाज में विस्तारित होकर समूचे पर्यावरण में प्रस्फुटित हो जाये। नदी प्रदूषण भी इसका बड़ा प्रभाव है। जलग्रहण क्षेत्र में रहने वाला जन जब तक स्वयं को रसायन मुक्त नहीं करेगा तब तक उससे निस्तारित जल नुकसानदायक रसायनों से मुक्त नहीं हो सकता।



**स्वस्थ परिवार - स्वस्थ भूमि - स्वस्थ नर्मदा मैया**



# नर्मदा समग्र

का त्रैमासिक प्रकाशन

वर्ष : 13 | अंक : 50

माह : अक्टूबर - दिसम्बर 2023

**संस्थापक संपादक** : स्व. अनिल माधव दवे

**संपादक** : कार्तिक सप्रे

**संपादकीय मण्डल** : डॉ. सुदेश वाघमारे  
संतोष शुक्ला

**आकल्पन** : संदीप बागड़े

**मुद्रण** : नियो प्रिंटर्स, 17-बी-सेक्टर,  
औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल

**सम्पर्क** : 'नदी का घर'  
सीनियर एम.आई.जी.-2, अंकुर कॉलोनी,  
शिवाजी नगर, भोपाल-462016

E-mail : narmada.media@gmail.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्री करण सिंह कौशिक द्वारा  
नियो प्रिंटर्स, 17-बी, सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र  
गोविन्दपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं नदी का घर  
सीनियर एम.आई.जी.-2 अंकुर कालोनी, पारूल  
अस्पताल के पास शिवाजी नगर, भोपाल-462016  
से प्रकाशित

**संपादक** : कार्तिक सप्रे। फोन : 0755-2460754

[f](https://www.facebook.com/narmadasamagra) @narmadasamagra [t](https://www.instagram.com/narmadasamagra) @narmada\_samagra

[i](https://www.instagram.com/narmadasamagra) @narmadasamagra [v](https://www.youtube.com/channel/UC...) @narmadasamagra

[in](https://www.linkedin.com/company/narmadasamagra) @narmadasamagra [www.narmadasamagra.org](http://www.narmadasamagra.org)

## इस अंक में .....

संपादकीय	05
कॉप १८ में उद्बोधन	06-09
प्रधानमंत्री का उद्बोधन	06
सीओपी-28 में केन्द्रीय पर्यावरण, वन...	07
जलवायु परिवर्तन को लेकर वर्षात समीक्षा	09
<b>आलेख</b>	11-17
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की...	11
जलवायु परिवर्तन की समस्या ओर भारत	13
कॉप 28 तेल के खेल में कालिख हासिल	16
<b>हेरिटेज ट्री</b>	18
खुरासनी इमली	18
<b>आलेख</b>	19-26
अमृत उत्सव मनाता गाँव नांदिया कला	19
हम अपनी पीढ़ियों को क्या स्वच्छ वातावरण...	23
स्वामी सदाचैतन्य (सादा बाबा) एक अनोखे...	24
नाम से ही नहीं कर्म से सादे थे सादा बाबा	26
<b>संस्मरण</b>	२7
सादा बाबा से परिक्रमा के समय मुलाकात	27
सादा बाबा के साथ बिताये कुछ समय...	27
<b>नर्मदा अंचल के वृक्ष</b>	२८-२९
कुसुम/कोसुम	28
<b>आलेख</b>	३०
नदी एम्बुलेंस पर नन्हें बालक सुरेश...	30
<b>पर्यावरण पंचकोसी यात्रा</b>	३१-३३
महाकौशल, नर्मदापुरम, मालवा निमाड़ भाग	31
<b>प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्द्धन</b>	३४-३७
औषधीय पौधों की पहचान, संरक्षण, संवर्धन...	34
वनों की अग्नि सुरक्षा करने का प्रशिक्षण	37
<b>प्रेरणा दिवस</b>	३९-४०
विजयादशमी स्व. अनिल माधव दवे	39
भागों में प्रेरणा दिवस की झलकियाँ	40
<b>अनुभूति</b>	41
नदी का घर अपने नाम के अनोखेपन से...	41
<b>गतिविधियाँ</b>	4२-4३
हायजिन कीट वितरणक कार्यक्रम	42
<b>संस्थापक की लेखनी से</b>	46
गोंड, बैगा, बारैला, कोरकू	46

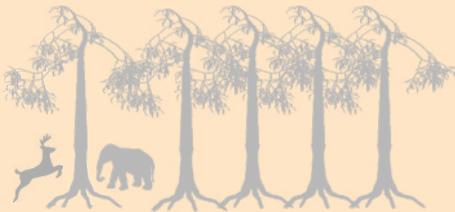


# पर्यावरण माने क्या?



स्व. श्री अमृतलाल वेगड़

3 अक्टूबर 1928 - 6 जुलाई 2018



‘पर्यावरण’ शब्द जरा कठिन है।

इससे पहले तुमने इसे सुना भी न हो।

शायद जलवायु शब्द सुना हो।

‘जल’ और ‘वायु’ से आधा पर्यावरण बन जाता है।

इसके साथ पेड़ ओर मिट्टी को भी जोड़ लो

तो समझो पूरा पर्यावरण हो गया।

‘पर्यावरण’ दो शब्दों से मिलकर बना है

‘परि’ और ‘आवरण’

‘परि’ माने घेरा, ‘आवरण’ माने पर्दा

इसलिए ‘पर्यावरण’ का मतलब हमें घेरने वाला पर्दा।

अर्थात् हमारे आस-पास का प्राकृतिक आवरण।

पर्यावरण यानी प्रकृति की वे सभी चीजें

जो जीने के लिए जरूरी हैं।

पवन, पानी और पेड़।

पशु, पक्षी, धरती, आकाश।

यही है पर्यावरण।

हम कहीं भी हों, हम ‘पर्यावरण’ में रहते हैं। □

- अमृतलाल वेगड़

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 के कार्यक्रमों में संवहनीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जलवायु परिवर्तन किसी एक देश या एक समाज पर प्रभाव नहीं डालता अपितु सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या इससे प्रभावित हो रही है। इसलिए प्रधानमंत्री का कथन कि एक ग्रह, एक परिवार और एक भविष्य अर्थात् 'वसुधैव कुटुम्बकम्' ही हमारा लक्ष्य है, एक समकालिन कथन है। इस बात की आवश्यकता है कि विकसित देश विकासशील देशों को तकनीक एवं आर्थिक सहायता प्रदान करें ताकि जलवायु के खतरों को टाला जा सके। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वर्षात समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 बनाये गये हैं जो भविष्य में प्रदूषण रोकने के लिए उल्लेखनीय योगदान देंगे। वर्षान्त समीक्षा में यह आकलन भी किया गया है कि भारत ने ऊर्जा के फॉसिल आधारित ईंधन के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत तरीकों से ऊर्जा का उत्पादन कर लक्ष्य प्राप्ति की है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर नियंत्रण करने तथा इंडिया कलिंग एक्शन प्लान जैसे नवाचार कर ओजोन परत के संरक्षण में लक्ष्य से अधिक ही भागीदारी की है। ऐसा कहा जाता है कि आशा से आकाश थमा है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक पृथ्वी, एक परिवार का सपना यथार्थ में परिणत होकर रहेगा।

जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, ओजोन परत का टूटना, कार्बन फुट प्रिन्ट, फॉसिल फ्यूल जैसे शब्द जब विश्व के रंगमंच पर सुनाई देते हैं तो भारत के आम आदमी को बहुत फर्क नहीं पड़ता। नदी, पर्वत, पहाड़, वन और वन्यजीवों के प्रति दया भावना हमारी जीवन शैली और संस्कृति का हिस्सा रहा है। यह अलग बात है कि कथित विकास और प्रगति की अंधी दौड़ ने जीवन मूल्यों का अवनमन किया है। इस सब के बावजूद भी हमारे देशवासी कार्बन उत्सर्जन में बड़ी हिस्सेदारी निभाते हैं। विश्व की कुल आबादी का 17% भारत में निवास करता है जबकि भारत की कुल आबादी जो कार्बन उत्सर्जन करती है वह मात्र 4% है। इसके बाद भी विकासशील देशों को ही कार्बन उत्सर्जन कम करने की सलाह दी जाती है।

कॉप-28 ( COP-28 ) की पड़ताल करते विषय विशेषज्ञों के तीन विशिष्ट लेख इसमें शामिल किये गये हैं। रमनकांत जी भारतीय नदी परिषद के संस्थापक हैं और नदियों तथा पर्यावरण पर उनका कार्य, चिन्तन और अनुभव समादूत है। जलवायु परिवर्तन की इस अन्तर्राष्ट्रीय समस्या में भारत विश्व को समाधान दिखा सकता है, यह उनके लेख का केन्द्रीय विचार है। दूसरा लेख सुश्री विभूति जोशी जी का है। वह न केवल जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं अपितु सिकोईडिकोन नामक संस्था के द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिये राजस्थान और समीपस्थ राज्यों में मैदानी स्तर पर सक्रिय हैं। उनके जैसे युवाओं का इस क्षेत्र में सक्रिय होना एक बड़ी आश्वस्ति है। वे अपने लेख में इस बात की भी पड़ताल करती हैं कि विश्व ने जो लक्ष्य 2030 के लिए निर्धारित किये थे, वे किस दिशा में जा रहे हैं। उनके अनुसार 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ भारत ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वे प्रधानमंत्री द्वारा उठाये गये मुद्दों का पूर्ण समर्थन करती हैं। अजय झा जी भी जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं और COP-28 के निष्कर्षों को अप्रत्याशित नहीं मानते। संयुक्त अरब अमीरात में 13 दिसम्बर 2023 को दुबई में समाप्त इस बैठक में विभिन्न देशों की सरकारों सहित 85,000 लोग सम्मिलित हुए हैं। मगर अजय झा एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करते हैं कि 'क्लाईमेट फाइनेंस' का क्या हुआ? यानि धनी देश गरीब यानि विकासशील देशों को जो धन और संसाधन देना चाहते थे, उनका क्या हुआ। शायद अगले कॉप में इस पर निर्णय हो।

नर्मदा समग्र, नर्मदा तट के विरासत वृक्ष बचाने और उनका संरक्षण करने के लिये कृत संकल्पित है। मांडव में पाई जाने वाली खुरासानी इमली के सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्षों पर भी एक आलेख इस अंक में सम्मिलित है। देश के पूर्व केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरणविद् एवं नर्मदा समग्र के प्रणेता अनिल माधव दवे जी, पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली का आग्रह सदैव करते रहें। जिनसे प्रेरणा लेकर असंख्य नर्मदा सेवक अपने-अपने स्तर पर इस वैश्विक जलवायु संकट के प्रभावों को कम करने हेतु यथासंभव पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। □

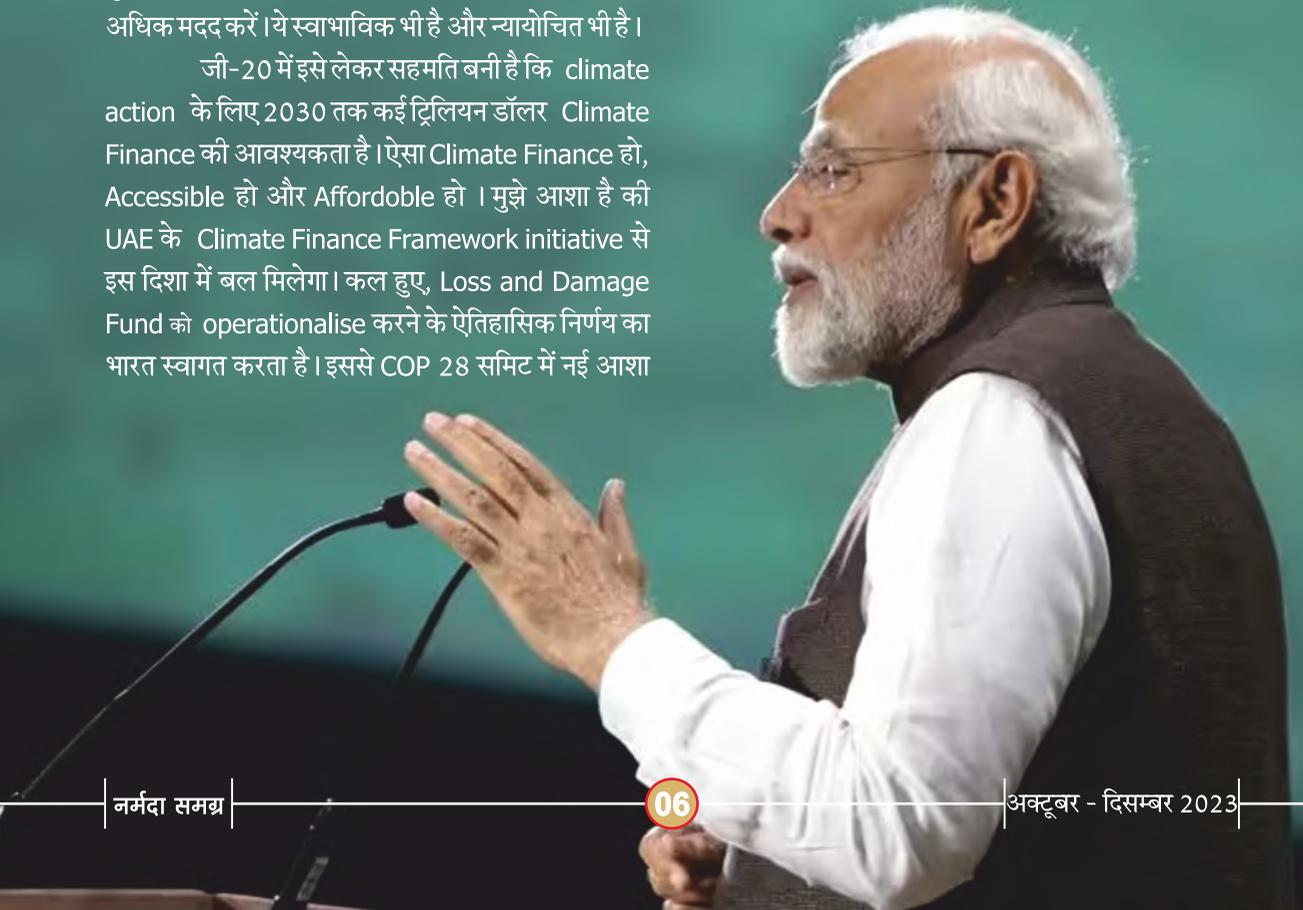
जी-20 अध्यक्षता में, भारत ने sustainable development और climate change इन दोनों विषयों को बहुत ही प्राथमिकता दी है।

हमने One Earth, One Family, One Future को अपनी अध्यक्षता का आधार बनाया। और साझा प्रयासों से, कई विषयों पर सहमति बनाने में भी सफलता पाई। हम सभी जानते हैं कि भारत सहित ग्लोबल साउथ के तमाम देशों की climate चेंज में भूमिका बहुत कम रही है। पर climate change के दुष्प्रभाव उन पर कहीं अधिक हैं। संसाधनों की कमी के बावजूद ये देश climate action के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए climate finance और टेक्नॉलॉजी बहुत ही जरूरी है। ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विकसित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें। ये स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है।

जी-20 में इसे लेकर सहमति बनी है कि climate action के लिए 2030 तक कई ट्रिलियन डॉलर Climate Finance की आवश्यकता है। ऐसा Climate Finance हो, Accessible हो और Affordable हो। मुझे आशा है कि UAE के Climate Finance Framework initiative से इस दिशा में बल मिलेगा। कल हुए, Loss and Damage Fund को operationalise करने के ऐतिहासिक निर्णय का भारत स्वागत करता है। इससे COP 28 समिट में नई आशा

का संचार हुआ है। हम उम्मीद करते हैं COP समिट climate finance से जुड़े अन्य विषयों पर भी ठोस परिणाम निकालेंगे। पहला, COP-28 में New Collective Quantified Goal on Climate Finance पर वास्तविक प्रगति होगी। दूसरा, Green Climate Fund और Adaptation Fund में कमी नहीं होने दी जाएगी, इस फंड की त्वरित भरपाई की जाएगी। तीसरा, Multilateral Development Banks, विकास के साथ साथ क्लाइमेट एक्शन के लिए भी अफोर्डेबल finance उपलब्ध कराएंगे। और चौथा, विकसित देश 2050 से पहले अपना कार्बन footprint जरूर खत्म करेंगे। मैं UAE द्वारा Climate Investment Fund स्थापित करने की घोषणा का हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। □





## सीओपी- 28 में केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मूपेन्द्र यादव का राष्ट्रीय वक्तव्य

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई में सीओपी-28 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया।

सबसे पहले मैं सीओपी-28 की मेजबानी और उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। भारत इस सीओपी को कार्रवाई के लिए सीओपी के रूप में संचालित करने के लिए सीओपी-28 अध्यक्षता को भी बधाई देता है, जो हानि और क्षति निधि के सफल संचालन के

साथ पहले ही दिन स्पष्ट हो गया। भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक स्तर पर कार्रवाई-उन्मुख कदमों का समर्थन करने में सबसे आगे रहा है। हमारा हमेशा से यह विचार रहा है कि लोग और ग्रह एक रहे हैं और मानव कल्याण व प्रकृति आंतरिक रूप से एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिशन लाइफ-पर्यावरण के लिए जीवन शैली में शामिल होने के लिए वैश्विक समुदाय का आशान किया था और यह भारत के कार्य-उन्मुख दृष्टिकोण का प्रमाण है।

भारत ने मिशन लाइफ के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए अभिनव पर्यावरण कार्यक्रमों और उपकरणों के आदान-प्रदान के लिए एक सहभागी वैश्विक मंच बनाने के उद्देश्य से 1 दिसंबर को यहां सीओपी-28 में हरित क्रेडिट पहल शुरू की। इस साल की शुरुआत में हमने नई दिल्ली घोषणा के एक हिस्से के तहत जी20 देशों की ओर से ऐतिहासिक रूप से हरित विकास समझौते को अपनाते हुए देखा।

अब भारत ने प्रारंभिक अनुकूलन संचार के साथ-साथ 2019 की जीएचजी (ग्रीन हाउस गैस) सूची

ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग करने के प्रयास के तहत भारत ने साल 2005 और 2019 के बीच अपने जीडीपी की तुलना में उत्सर्जन की तीव्रता को 33 फीसदी तक सफलतापूर्वक कम कर दिया है। इस तरह भारत ने 2030 के लिए प्रारंभिक एनडीसी लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा से 11 साल पहले प्राप्त कर लिया है।

के आधार पर अपने तीसरे राष्ट्रीय संचार को अंतिम रूप दिया है। यह लोगों के विकास और कल्याण को प्राथमिकता में रखते हुए जलवायु कार्रवाई को लेकर हमारे निरंतर योगदान को रेखांकित करता है।

ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग करने के प्रयास के तहत भारत ने साल 2005 और 2019 के बीच अपने जीडीपी की तुलना में उत्सर्जन की तीव्रता को 33 फीसदी तक सफलतापूर्वक कम कर दिया है। इस तरह भारत ने 2030 के लिए प्रारंभिक एनडीसी लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा से 11 साल पहले प्राप्त कर लिया है।

भारत ने साल 2030 के लक्ष्य से नौ साल पहले गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों के माध्यम से विद्युत की 40 फीसदी स्थापित क्षमता भी प्राप्त कर ली है। साल 2017 और 2023 के बीच भारत ने लगभग 100 गीगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता जोड़ी है, जिसमें से लगभग 80 फीसदी गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित संसाधनों से संबंधित है। हमने अपने एनडीसी के लक्ष्य को संशोधित कर बढ़ाया है, जो जलवायु कार्रवाई में बढ़ोतरी को लेकर हमारी



गहरी प्रतिबद्धता को दिखाता है। अपनी घरेलू पहलों के अलावा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई), लीडआईटी का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स (आईआरआईएस) और बिग कैट गठबंधन जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से जलवायु कार्रवाई में भारत का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का गठन इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में जी20 नेताओं की बैठक के दौरान किया गया था। इसका उद्देश्य जैव ईंधन की बढ़ोतरी और उसे व्यापक रूप से अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने वाले

एक उत्प्रेरक मंच के रूप में काम करना है।

जैसा कि हम यहां सीओपी-28 के लिए दुबई में इकट्ठे हुए हैं, भारत वैश्विक हिस्सेदारी के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है और आशा करता है कि वे बढ़ी हुई जलवायु कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए सार्थक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेंगे।

नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य के तहत संसाधन जुटाना विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप निर्देशित होना चाहिए। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि समानता और जलवायु न्याय वैश्विक जलवायु कार्रवाई का आधार होना चाहिए। यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब विकसित देश महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई में आगे आएंगे। इस सम्मेलन और इसके पेरिस समझौते के सिद्धांतों व प्रक्रियाओं में अपना भरोसा और विश्वास बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण है। चूंकि हमारी पृथ्वी एक है, हम एक परिवार हैं और एक भविष्य साझा करते हैं, इसलिए आइए हम सभी हरित, स्वच्छ और स्वस्थ पृथ्वी के लिए साझा उद्देश्य को लेकर मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। □

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जलवायु परिवर्तन को लेकर वर्षात समीक्षा

## हरित क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी)

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सीओपी-28 के अवसर पर ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया गया था। यह पर्यावरण के लिए जीवनशैली अथवा लाइफ आंदोलन के अंतर्गत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 12 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया है। ये नियम स्वैच्छिक पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए एक व्यवस्था को स्थापित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी किए जाते हैं। इसके प्रारंभिक चरण में वन विभाग के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अंतर्गत निम्नीकृत भूमि, बंजर भूमि, जलग्रहण क्षेत्र आदि पर स्वैच्छिक पौधरोपण की अवधारणा की गई है।

ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट का सृजन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के तहत प्रदान किये गए कार्बन क्रेडिट से स्वतंत्र रूप से संचालित है। जीसीपी की शासन व्यवस्था में संबंधित मंत्रालयों/विभागों, विशेषज्ञों और संस्थानों के संचालन समिति के सदस्य शामिल हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को जीसीपी प्रशासक के रूप में नामित किया गया है और यह जीसीपी के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। जीसीपी

की डिजिटल प्रक्रिया में परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए समर्पित वेब प्लेटफॉर्म और जीसी रजिस्ट्री भी शामिल है। इन पद्धतियों और दिशा-निर्देशों के अलावा इस प्रक्रिया में पंजीकरण, लेखांकन और जीसी जारी करने की निगरानी सहित जीसीपी की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

## एनडीसी लक्ष्यों के मुकाबले भारत की उपलब्धियां

वर्ष 2015 में प्रस्तुत भारत के प्रथम राष्ट्रीय स्तर के निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुसार, भारत का निम्नलिखित लक्ष्य था:

2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना; और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना।

ये दोनों लक्ष्य समय से काफी पहले हासिल कर लिए गए हैं। 31 अक्टूबर, 2023 तक, गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल संचयी विद्युत स्थापित क्षमता 186.46 मेगावाट है, जो कुल संचयी विद्युत स्थापित क्षमता का 43.81 प्रतिशत है। 2005 से 2019 के बीच देश में जीडीपी के उत्सर्जन स्तर को 33 प्रतिशत कम कर लिया गया है। भारत ने

अपने एनडीसी को अद्यतन किया, जिसके अनुसार उसके सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सघन उत्सर्जन में कटौती करने के मद्देनजर लक्ष्य को 2005 के स्तर से 2030 तक 45 प्रतिशत तक बढ़ाना है। इसके अलावा गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से पैदा होने वाली बिजली की निर्धारित क्षमता को 2030 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

## संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 28वां सत्र (सीओपी-28)

भारत के एक अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधि मंडल ने 30 नवंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी 28) के 28वें सत्र में भाग लिया। सीओपी 28 के प्रमुख परिणामों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से लिए गए फैसलों पर निर्णय, दशक के अंत से पहले वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाना और हानि एवं क्षति निधि के संचालन पर समझौता करना शामिल है। इन वैश्विक प्रयासों को देशों द्वारा पेरिस समझौते और उनकी विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय संचार को 9 दिसंबर, 2023 को प्रस्तुत

किया गया। इस रिपोर्ट में भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन के प्रति इसकी संवेदनशीलता और उत्सर्जन को कम करने तथा अनुकूलन के लिए उठाए जा रहे उपायों की जानकारी शामिल है। जलवायु परिवर्तन पर होने वाले प्रभावों में सर्वाधिक समग्र रूप से मानवजनित उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र ने 75.81 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक योगदान दिया है, इसके बाद कृषि क्षेत्र ने 13.44 प्रतिशत, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग (आईपीपीयू) ने 8.41 प्रतिशत तथा अपशिष्ट ने 2.34 प्रतिशत के साथ योगदान दिया है।

**भारत ने यूएनएफसीसीसी के लिए प्रारंभिक अनुकूलन संचार भी प्रस्तुत किया।** भारत मिशन मोड में अनुकूलन की दिशा में पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अनुकूलन गतिविधियों के व्यापक दायरे को ध्यान में रखते हुए प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में कई नीतियों और उपायों को कार्यान्वित किया गया है। विकासशील अर्थव्यवस्था में सीमित संसाधनों की प्रतिस्पर्धी मांगों के बावजूद, भारत अनुकूलन संबंधी कार्यों पर महत्वपूर्ण मात्रा में संसाधनों का व्यय कर रहा है। 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाईफ का भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया था। 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी सीओपी 26) में, माननीय प्रधानमंत्री ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्रवाई में सकारात्मक सुधार के लिए व्यक्तिगत व्यवहार को अग्रणी रखने के लिए मिशन

लाईफ की घोषणा की। लाईफ को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसमें आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन 2022, जलवायु परिवर्तन शमन कार्य समूह III रिपोर्ट, 2022, शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना, 2022 में शामिल निर्णय, सापोरो, जापान 2023 में अपनाया गई जी7 विज्ञप्ति, शंघाई सहयोग संगठन विज्ञप्ति, 2023, जी20 लीडर्स डिक्लरेशन, 2023 और 9वां जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी20) एवं संसदीय मंच, 2023 शामिल हैं।

### इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान

भारत एक व्यापक कूलिंग एक्शन प्लान तैयार करने वाला विश्व का प्रथम देश है, जो अन्य बातों के साथ-साथ 20 वर्ष की निर्धारित समयावधि में कूलिंग की मांग को कम करने, रेफ्रिजरेंट संक्रमण, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्पों को शामिल करते हुए सभी क्षेत्रों में कूलिंग की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज ऑउट मैनेजमेंट प्लान (एचपीएमपी) चरण-II के कार्यान्वयन के दौरान, भारत ने कठोर फोम के निर्माण में हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी)-141बी के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और भारत इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाले विकासशील देशों में पहला देश है। 1 जनवरी, 2020 को निर्धारित लक्ष्य से 35 प्रतिशत की कमी के लक्ष्य के

मुकाबले, भारत ने 44 प्रतिशत की कमी हासिल की और यह समतापमंडलीय ओजोन परत के संरक्षण में भारत के प्रयासों को प्रदर्शित करता है।

### भारत की अध्यक्षता में जी-20 वरुल

**पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी)** गांधीनगर कार्यान्वयन रोडमैप और गांधीनगर सूचना मंच (जीआईआर-जीआईपी) के तहत जंगल की आग और खनन प्रभावित क्षेत्रों की भूमि बहाली पर एक वैश्विक गठबंधन की शुरुआत। संसाधन दक्षता चक्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक गठबंधन (आरईसीईआईसी) को भारत की अध्यक्षता में दुनिया भर के निजी क्षेत्र के 40 संस्थापक सदस्यों के साथ शुरू किया गया था। टिकाऊ और लचीली नीली/महासागर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए उच्च-स्तरीय व्यवस्था (एचएलपीएसआरबीई) को प्रारंभ किया गया। जी-20 देशों ने औपचारिक रूप से 9 व्यापक उच्च-स्तरीय सिद्धांतों को अपनाया। इसमें, एचएलपीएसबीई के अनुसार, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री स्थानिक योजना की तैयारी के लिए बेसलाइन अध्ययन शामिल है।

21 मई, 2023 को एक विशाल समुद्र तट सफाई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 18 देशों ने भाग लिया। 20 अंतरराष्ट्रीय समुद्र तटों पर कुल 3300 स्वयंसेवकों ने भाग लिया और सभी समुद्र तटों से 3593 किलोग्राम कचरा एकत्र किया गया। □



**विमूति जोशी**

(लेखक - विकास और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, सेंटर फॉर क्लाइमेट इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कैसल्टेट्स सोसाइटी (सिकोईडिकोन) कार्यरत।)

COP28 में राष्ट्राध्यक्षों, पर्यावरण मंत्रियों और 70000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों सहित अभूतपूर्व स्तर की भागीदारी देखी गई। इस हाई-प्रोफाइल उपस्थिति ने वैश्विक मंच पर जलवायु मुद्दों के बढ़ते राजनीतिक महत्व को रेखांकित किया।

संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएन एफसीसीसी) की पार्टियों का 28वां सम्मेलन (सीओपी28) भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह आयोजन पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के साथ विकास संबंधी आकांक्षाओं को संतुलित करने की देश की चल रही यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सीओपी सम्मेलन वैश्विक जलवायु नीतियों और कार्यों को आकार देने के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुए हैं। COP28 में भारत की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय थी, क्योंकि इसने वैश्विक जलवायु चर्चा में निष्पक्षता और समता

के सिद्धांतों की वकालत करते हुए अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

COP28 के प्रमुख परिणामों में से एक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की गति बढ़ाने पर जोर देना था। इस लक्ष्य को विभिन्न देशों ने दोहराया, जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों से निपटने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

भागीदारी के संदर्भ में, COP28 में राष्ट्राध्यक्षों, पर्यावरण मंत्रियों और 70000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ विभिन्न देशों के

प्रतिनिधियों सहित अभूतपूर्व स्तर की भागीदारी देखी गई। इस हाई-प्रोफाइल उपस्थिति ने वैश्विक मंच पर जलवायु मुद्दों के बढ़ते राजनीतिक महत्व को रेखांकित किया। सम्मेलन ने देशों को जलवायु प्रतिबद्धताओं पर अपनी प्रगति साझा करने, चुनौतियों पर चर्चा करने और स्थायी भविष्य के लिए सहयोगी रणनीतियाँ बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया।

भारत की जलवायु कार्य योजना पेरिस समझौते के तहत उसके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) पर आधारित है। 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, गैर-जीवाश्म बिजली उत्पादन में वृद्धि और नए कार्बन सिंक के निर्माण सहित ये प्रतिबद्धताएँ, जलवायु परिवर्तन शमन की दिशा में वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत के प्रयास को दर्शाती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत ने पहले ही इनमें से कई क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की है। उदाहरण के लिए, यह 2023 के मध्य तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंच गया है, जिससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में अग्रणी देशों में से एक बन गया है।

हालाँकि, कोयले पर निर्भरता का मुद्दा भारत के लिए एक जटिल विषय है। नवीकरणीय ऊर्जा में अपनी प्रगति के

बावजूद, देश ने जल्द ही कोयला-जनित बिजली को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया है। यह निर्णय भारत की अद्वितीय विकासात्मक चुनौतियों और इसकी बड़ी आबादी के लिए ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर आधारित है। आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए इस परिवर्तन को संतुलित करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

सीओपी चर्चाओं के प्रति भारत के दृष्टिकोण में समानता और जलवायु न्याय केंद्रीय विषय रहे हैं। देश ने लगातार साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी (सीबीडीआर) सिद्धांत की वकालत की है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि वैश्विक उत्सर्जन में बड़े ऐतिहासिक योगदान वाले विकसित देशों को जलवायु शमन में अधिक बोझ उठाना चाहिए और वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विकासशील देशों का समर्थन करना चाहिए।

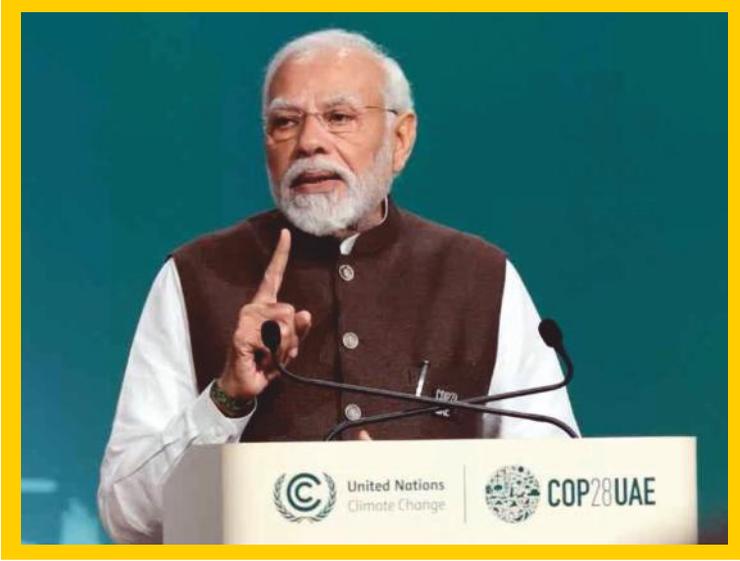
COP28 में जलवायु वित्त का विषय विशेष रूप से प्रमुख था। लॉस एंड डैमेज फंड (एलडीएफ) के लॉन्च ने जलवायु संबंधी आपदाओं के लिए वित्तीय जिम्मेदारी पर चल रही बहस पर प्रकाश डाला। हालाँकि एलडीएफ को चालू करने के समझौते को इस सीओपी के एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में स्वीकार किया गया है लेकिन इसमें अभी भी ठोस वित्तीय प्रतिबद्धताओं का अभाव है। कुछ विकसित देशों द्वारा

विभिन्न मूल्यांकनों के आधार पर वर्तमान आवश्यकताओं का 1% से भी कम प्रतिबद्ध किया गया है। अन्य विकासशील देशों के साथ-साथ भारत ने इन प्रयासों के समर्थन में विकसित देशों से अधिक ठोस और स्पष्ट प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता पर बल दिया है।

सीओपी प्रक्रिया में भारत का विकास उल्लेखनीय है। 2002 में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण COP28 की मेजबानी से लेकर हाई-प्रोफाइल COP28 में सक्रिय रूप से भाग लेने तक, भारत ने लगातार पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। 2028 में भारत के COP33 की मेजबानी करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी अपेक्षित वृद्धि के साथ, इस प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

संक्षेप में, COP28 ने भारत के लिए न केवल जलवायु कार्रवाई में अपनी उपलब्धियों और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया, बल्कि एक वैश्विक जलवायु कार्रवाई ढांचे का समर्थन भी किया जो न्यायसंगत और उचित हो। इस यात्रा में भारत के सामने आने वाली चुनौतियाँ पर्यावरणीय स्थिरता की अनिवार्यता के साथ विकासात्मक आवश्यकताओं को संतुलित करने के व्यापक वैश्विक संघर्ष को दर्शाती हैं। □

# जलवायु परिवर्तन की समस्या और भारत



रमन खान्दा

(लेखक - रिवरमैन आफ इण्डिया  
संस्थापक - भारतीय नदी  
परिषद्।)

जैसी कि आशंका जताई जा रही थी, कोप 28 का दुबई सम्मेलन बगैर किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गया. जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों व उनसे निपटने के लिए कान्फ्रेंस आफ पार्टीज की 28 वीं बैठक में विश्व के

नेताओं का जमावड़ा संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में लगा था। करीब दो सप्ताह तक चलने वाले इस मंथन से आशा तो की जा रही थी कि भविष्य के लिए कुछ ठोस व सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे लेकिन प्रत्येक कोप की बैठक की तरह आशंकाएं भी थीं कि कहीं फिर से 'ढाक के तीन पात' न हो जाएं, और वही हुआ भी. विकसित अर्थात पर्यावरण को बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाने वाले देश अपनी मस्ती व मद में चूर रहकर समस्या के ठोस

समाधान के लिए गंभीर दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये देश कोप की बैठकों में शामिल तो होते हैं लेकिन इसकी सहमतियों पर अमल नाम मात्र का ही करते हैं, यही कारण है कि समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। कभी-कभी अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश तो अपनी सहूलियत के अनुसार मौसम परिवर्तन की समस्या को ही नकार देता है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एन्टोनियो गुटेरस ने पहले ही आगाह कर दिया है कि अगर हमें अपनी पृथ्वी को पिघलने से रोकना है जलवायु परिवर्तन हेतु मिलकर ठोस कदम उठाने ही होंगे। यह जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है कि अंटार्कटिका जैसा सोता हुआ महादानव भी अब जागने लगा है। इस समय पृथ्वी व मानव का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है ऐसे में कोप28 से उम्मीद की जा रही थी कि सभी देश इस विशालकाय समस्या हेतु अपने-अपने स्तर से ठोस प्रयास प्रारम्भ करेंगे। गुटेरस के अनुसार दुबई में आयोजित हुए कोप28 में चार बिन्दुओं पर सहमति बनाने तथा उन पर कार्य करने का प्रयास किया गया। इन बिन्दुओं में 2030 से पहले ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाना और उत्सर्जन में कटौती करना, पुराने वादों को पूर्ण करके नए मानक तय करना, प्रकृति, लोगों व आजीविका को भी जलवायु परिवर्तन के केन्द्र में रखकर देखना तथा एक समावेशी कोप संगठन बनाना शामिल था. गुटेरस स्वयं मानते हैं

जलवायु परिवर्तन की समस्या अब नंगी आखों से भी सभी को दिखने लगी है। वर्ष-प्रतिवर्ष नदियों में आती भयंकर बाढ़ तथा उनमें अचानक होने वाली पानी की कमी, सूखे छेत्रों में वर्षा की बहुलता तथा हरे-भरे क्षेत्रों में पड़ता सूखा, पहाड़ों का खिसकना, रोज नए तूफानों का आना, बेमौसम बरसात, कम समय में अधिक वर्षा, अत्यधिक गर्मी, भयंकर सर्दी, पहाड़ों पर गर्मी का बढ़ना तथा मैदानी क्षेत्रों में सर्दी का बढ़ता प्रभाव ये सब ऐसा हो रहा है जोकि अप्रत्याशित है। इन सब का असर जहां फसलों व प्रकृति पर पड़ रहा है वहीं मानव जीवन इनसे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की समस्या विकराल होती जा रही है उसके लिए हमारे समाधान नकाफी सिद्ध हो रहे हैं। अगर हमने सुधारों में तेजी नहीं दिखाई तो हमारा व पृथ्वी का भविष्य अधर में है।

जलवायु परिवर्तन की समस्या अब नंगी आखों से भी सभी को दिखने लगी है। वर्ष-प्रतिवर्ष नदियों में आती भयंकर बाढ़ तथा उनमें अचानक होने वाली पानी की कमी, सूखे छेत्रों में वर्षा की बहुलता तथा हरे-भरे क्षेत्रों में पड़ता सूखा, पहाड़ों का खिसकना, रोज नए तूफानों का आना, बेमौसम बरसात, कम समय में अधिक वर्षा, अत्यधिक गर्मी, भयंकर सर्दी, पहाड़ों पर गर्मी का बढ़ना तथा मैदानी क्षेत्रों में सर्दी का बढ़ता प्रभाव ये सब ऐसा हो रहा है जोकि अप्रत्याशित है। इन सब का असर जहां फसलों व प्रकृति पर पड़ रहा है वहीं मानव जीवन इनसे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोगों की आजीविका व उनका स्वास्थ्य भी संकट में पड़ रहा है। अभी भी हम पृथ्वी के वैश्विक तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने में कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते हम उसके लिए गंभीर पहल करें, लेकिन ऐसा होता



नहीं दिख रहा है और हम धीरे-धीरे 3 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान की वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।

कोप 28 के उद्घाटन सत्र के अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित कोप26 के अपने संकल्प को पुनः दोहराया था. उन्होंने कहा कि पंचामृत के माध्यम से वर्ष 2030 तक की चार प्रतिबद्धताओं (नोन फोसिल फयूल एनर्जी क्षमता को 500 गीगावाटर तक पहुँचाना, 45 प्रतिशत कार्बन एमीशन को कम करना, अपनी उर्जा जरूरत की 50 प्रतिशत सौर उर्जा से पूरा करना, कार्बन एमीशन में एक बिलियन टन की कमी करना) के

साथ वर्ष 2070 तक भारत के नेट जीरो के संकल्प को आगे बढ़ाना ही होगा। नरेन्द्र मोदी ने विकसित देशों की खिंचाई करते हुए यह भी कहा था कि भारत में विश्व की कुल 17 प्रतिशत आबादी निवास करती है जबकि भारत की कार्बन उत्सर्जन में हिस्सेदारी मात्र 4 प्रतिशत है। इस सबके बावजूद भी भारत यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नेशनल डिटरमाइंड कन्ट्रीब्यूशन के तहत तय लक्ष्यों पर गंभीरता से आगे बढ़ रहा है।

इस क्रम में भारत ने नई दिल्ली में आयोजित सी20 सम्मेलन में अपनी संस्कृति व मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए



एक पृथ्वी-एक परिवार-एक भविष्य का नारा दिया था। यहीं से मिशन लाइफ अर्थात् पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली का भी मंत्र भारत द्वारा विश्व को दिया गया था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार मिशन लाइफ के प्रभाव से वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष करीब 2 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है।

जी20 में ही भारत द्वारा ग्रीन डवलपमेंट पैक्ट पर भी सहमति बनाई गई और ग्लोबल बायोफ्यूएल एलाइंस की घोषणा भी की गई। यहीं पर भारत की ओर से विकसित देशों को पुनः याद दिलाया गया कि वे क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट पर अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार आगे बढ़ते हुए प्रभावित, गरीब व विकासशील देशों को आर्थिक मदद का अपना वादा निभाएं। ये देश ग्लोबल कार्बन बजट के तहत गरीब, प्रभावित व विकासशील देशों को मदद करें, क्योंकि विकसित अर्थात् अधिक कार्बन

उत्सर्जन करने वाले देशों के चलते सबसे अधिक प्रभावित ग्लोबल साउथ के ही देश हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि मौसम परिवर्तन के यू0एन0 फ्रेमवर्क के तहत कार्य करते हुए नए-नए नवाचार किए जाएं तथा उन नवाचारों की तकनीक को जरूरतमंद देशों को भी दिया जाए। यह भी सर्वविदित है कि मौसम परिवर्तन की समस्या को सबसे अधिक समुन्द्रों के किनारे बसे देश झेल रहे हैं तथा आगे भी झेलने वाले हैं ऐसे में आवश्यक है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर रिजिलिएंस इनीसिएटिव के तहत आइलैण्ड के देशों को मदद की जाए। भारत इसमें बड़ी पहल करते हुए करीब 13 आइलैण्ड देशों में विकास के प्रोजेक्ट संचालित कर रहा है। भारत ने दुबई से प्रोप्लानेट-प्रोएक्टिव-पोजिटिव इनीसिएटिव का नया सूत्र दिया है। इसके तहत ग्रीन क्रेडिट इनीसिएटिव को आगे बढ़ाया जाना चाहिए अर्थात् जन-भागीदारी के माध्यम से सभी देशों को

अपने यहां कार्बन सिंक का निर्माण करना चाहिए।

भारत जलवायु परिवर्तन की वर्तमान समस्या के समाधान का रास्ता विश्व को दिखा सकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के मूल में ही प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर जीना है। इस समस्या का समाधान दो स्तरों से प्रारम्भ करना होगा। आज समस्या हमारे सामने है और किसी हद तक उसको पैदा करने वालों की भी पहचान विश्व कर चुका है। ऐसे में जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करनी ही चाहिए और समस्या पैदा करने वालों को भी अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए। जहां तक बात समस्या के स्थाई समाधान की है या समस्या पैदा ही न हो तो भारत का ज्ञान उसके लिए काफी है। इसका प्रारम्भ प्रत्येक व्यक्ति व परिवार से करना होगा। इसके लिए उपभोक्तावाद में कमी करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें समाज सुधारकों की बड़ी भूमिका तय की जानी चाहिए। योग, रसायनमुक्त कृषि, उर्जा बचत, स्वच्छ उर्जा उपयोग तथा यात्राओं में कमी भी जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान की अहम कड़ी साबित होगा। भारत ने वर्ष 2028 में होने वाले कोप33 को अपनी मेजबानी करने का प्रस्ताव भी कोप28 के मंच से रखा है। जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या से निपटने के लिए अगर विश्व भारतीय संस्कृति का अनुसरण करके आगे बढ़ता है तो विश्व का स्थाई समाधान अवश्य प्राप्त होगा। □

# काँप 28; तेल के खेल में कालिख हासिल



अजय झा

(लेखक - जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, निदेशक पब्लिक एडवोकेसी इनिशिएटिव्स फॉर राइट्स एंड वेल्थ इन इंडिया, नई दिल्ली।)

जलवायु परिवर्तन की 28वीं अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक बैठक 13 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में खत्म हुई। सरकारों सहित पूरी दुनिया से करीब 85 हजार लोग शामिल हुए। इस हिसाब से यह अब तक की सबसे बड़ी बैठक थी। बड़ी बैठक, बड़ी अपेक्षाएं, बड़े वायदे लेकिन हासिल शायद रेगिस्तान की रेत से ज्यादा कुछ भी नहीं।

यह बैठक 30 नवंबर को शुरू हुई और पहले दिन ही यह हल्ला मचा कि क्षतिपूर्ति निधि (लॉस एण्ड डैमिज फंड) को क्रियाशील कर दिया गया है। कुछ लोग उत्साहित भी हुए। हालांकि जब आप गहराई से देखेंगे तो

उत्साह कम और निराशा अधिक होगी। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्षतिपूर्ति के लिए एक फंड बनाना विकासशील व छोटे देशों और खासकर द्वीपीय देशों के लिए महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि यह चर्चा बिना किसी निष्कर्ष के तीस साल से चल रही थी। आशय यह था कि जिन देशों ने पूरी दुनिया से जीवाश्म ऊर्जा पर कब्जा करके उसकी खपत की - जिससे सभी पर यह जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं का संकट आया - उन विकसित, औद्योगिकृत और धनी देशों को गरीब देशों पर इस आपदा से जूझने के लिए क्षतिपूर्ति करना चाहिए। हालांकि कालांतर में यह चर्चा 'क्षतिपूर्ति' से 'एकजुटता' पर आ गई। अब यह गरीब, छोटे, द्वीपीय देश कभी भी विकसित औद्योगिकृत देशों से क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकते। काँप 28 में कुछ धनी देशों ने 700 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि क्षतिपूर्ति के लिए देने की मंशा जाहिर की। इसमें

कितनी राशि गरीब देशों तक पहुंचेगी, कब तक पहुंचेगी, यह तय नहीं है। यह भी तय नहीं है कि इसमें कितनी राशि कर्ज के रूप में दी जाएगी और कितनी दान के रूप में। कौन इसका हकदार हो सकता है यह भी निश्चित होना बाकी है। कई अनुमानों के मुताबिक विकासशील देशों की आवश्यकता तकरीबन 400 बिलियन डॉलर है और इस फंड में धनी देशों का योगदान पूर्णतः स्वैच्छिक है। जब जो जितना दे दे, न दे, सब उनकी नैतिकता पर निर्भर है। शायद यह सेठ की टेबल से गिरे टुकड़ों से ज्यादा नहीं है।

इसके अलावा सर्वाधिक गुणगान 'जीवाश्म ईंधन से दूर जाने' (Transitioning Away From Fossil Fuel) का हुआ। काँप 28 के निर्णय में पहली बार जीवाश्म ईंधन से दूर जाने को कागज पर लाने की धनी देशों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। यह बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जलवायु संकट का मूल कारण जीवाश्म ईंधन की

अत्यधिक खपत है और इस तथ्य को विचार से कागज पर आने में 30 साल का समय लगा।

आईपीसीसी का मानना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2050 तक जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जन का 90-95 प्रतिशत तक कम करना पड़ेगा। इस निर्णय से इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास को कोई गति मिलेगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता। उल्टा कॉप 28 ने प्राकृतिक गैस (जीवाश्म ईंधन) के इस्तेमाल को एक संक्रमणकालीन ईंधन के रूप में प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही इस कॉप 28 ने कार्बन कैप्चर एण्ड स्टोरेज जैसे विवादास्पद और झूठे समाधान को भी वैधता दी। स्पष्ट संदेश है कि जीवाश्म ईंधन लॉबी ने निर्णय को काफी हद तक प्रभावित किया। इस संदर्भ में यह कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जहां गरीब देशों में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सहमत बन जाती है, वहाँ अमीर देशों के तेल और गैस के प्रयोग पर रोक लगाना मुश्किल है। जीवाश्म ईंधन के आधे उत्सर्जन तेल और गैस से होते हैं लेकिन तेल और गैस का उत्पादन व निर्यात करने वाले दुनिया के 20 देशों में से किसी ने भी अब तक उसके उत्पादन या निर्यात पर कोई कमी करने की वास्तविक कोशिश नहीं की है। स्पष्ट है कि सारे कानून गरीब देशों के लिए हैं, अमीर देशों की जीवनशैली या मुनाफे से कोई समझौता नहीं है।

कॉप 28 में देशों ने यह भी

निर्णय लिया कि 2030 तक ऊर्जा दक्षता को दोगुना और अक्षय ऊर्जा को तिगुना किया जाए। यह अच्छा निर्णय है लेकिन इसका कार्यान्वित करने के लिए पैसा कौन देगा! सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उत्पादन अब काफी सस्ता हो गया है लेकिन इसके लिए आवश्यक बड़ी अग्रिम लागत पर बिना किसी आर्थिक सहायता के निवेश करना गरीब देशों के लिए असंभव है।

विकासशील देशों को आर्थिक संसाधन देने के सवाल को कॉप 28 ने एक और साल के लिए टाल दिया। 2009 का वादा कि विकासशील देशों को 2020 तक 100 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जाएगा, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बड़े प्रदूषक देशों की उत्सर्जन कम करने और संसाधन उपलब्ध कराने की नाकामी के कारण विकासशील देशों की जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनेंस) की आवश्यकता कई ट्रिलियन (3.5 ट्रिलियन डॉलर प्रतिवर्ष) हो चुकी है। धनी देश विकासशील देशों को कितना संसाधन देंगे, यह 2025 में तय होगा। कॉप में अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्यों पर बात तो हुई लेकिन इसमें भी अनुकूलन के लिए आर्थिक संसाधन की बातचीत नदारद थी। विकासशील देशों में उत्सर्जन तो कम है लेकिन अनुकूलन और उसके लिए संसाधन बड़ी आवश्यकता हैं। ऐसा आकलन है कि अनुकूलन के लिए उपलब्ध पैसे को दोगुना भी कर दिया जाए तो यह आवश्यकता के हिसाब से

बूंद बराबर होगा।

यह बैठक ऐसी परिस्थिति में हुई जहां कोविड महामारी अभी भी विद्यमान है, रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव अभी भी ईंधन, खाद्यान्न, खाद और आर्थिक संकट पर गहरा है, इजराइल द्वारा फिलीस्तीन का दमन जारी है, दुनिया के सारे देश अमरीका, चीन व रूस की तनातनी में खेमों में बंटे हुए हैं और आर्थिक मंदी, मुद्रा स्फीति, ऋण पर बढ़ते हुए ब्याज और ऋण के राष्ट्रीय संकट से जूझ रहे हैं। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक 152 में से 136 विकासशील देश गंभीर कर्ज से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी विकासशील देश 2022 में 440 बिलियन डॉलर का ऋण सेवा भुगतान करने पर मजबूर हैं। इस साल में जुलाई में राष्ट्रसंघ की एक बैठक ने यह भी बताया है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों में से शायद 15 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त किए जा सकेंगे, एक तिहाई लक्ष्य उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं और मौजूदा हालात में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में चार दशक और लग सकते हैं। इन चिंताओं पर कॉप 28 की बैठक में कोई खास चर्चा नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि कॉप 28 के निष्कर्ष अप्रत्याशित थे। अमीरात दुनिया के तेल उत्पादन 7वें और गैस उत्पादन में 14वें स्थान पर है। जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाने की अपेक्षा रखना भूल होगी। अगले वर्ष यह बैठक एक और तेल उत्पादक देश अजरबैजान में होगी। निष्कर्ष आप अभी ही निकाल सकते हैं। □

# क्या आपके आसपास भी है ऐसा कोई बड़ा-पुराना विरासत वृक्ष ? "Heritage Tree"

खुरासानी इमली - *Adansonia digitata*

अगर है तो आप भी उसे आलिंगन कर उसका चित्र सोशल मीडिया #Heritage Tree हैशटैग का प्रयोग कर, पेड़ का नाम, स्थान, लगभग कितना पुराना है, उससे जुड़ी कोई रोचक बात हो तो अवश्य शेयर करें।

विगत माह पुनः पर्यटन नगरी मांडव ( धार जिला ) जाने का अवसर मिला, वैसे तो पहले भी कई बार गए हैं लेकिन इस बार हम जहाँ रुके थे। हॉटल रूपमती। उसी के परिसर में एक विशालकाय वृक्ष ने मन बांध लिया, पेड़ था खुरासानी इमली का। मांडू मे पहले भी देखा है लेकिन इस बार तने की परिधि ने रोक लिया। हॉटल मैनेजर से पेड़ के बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने भी बड़े ही उत्साह के साथ जानकारी उपलब्ध कराई। आप जो वृक्ष देख रहे हैं यह लगभग 2000 वर्ष पुराना है। हम पांच लोग मिलकर भी इसके तने की परिधि को बहुत ही मुश्किल से अपने हाथों की सीमा में समेट पाए हैं।



खुरासानी इमली के बारे में कुछ रोचक बातें जान लेते हैं - खुरासानी इमली हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के शुष्क प्रदेश में उगने वाला 'बाओबाब' है। इसे 14वीं शताब्दी में महमूद खिलजी के शासनकाल के दौरान मांडव लाया गया था और इसका नाम 'बाओबाब' से बदलकर खुरासानी इमली कर दिया गया था। इसे अन्य नाम मांडव इमली और

अफगानी इमली के नाम से भी जाना जाता है। यह पेड़ ऐसा लगता है मानो किसी ने इसे उल्टा लगा दिया हो। जड़ें ऊपर और तना नीचे, पत्तियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही बढ़ती हैं। कहा जाता है कि इस फल को खाने के बाद 3-4 घंटे तक प्यास नहीं लगती है। फ्रांसीसी प्रकृतिवादी और खोजकर्ता मिशेल एडनसन के अनुसार इस पेड़ के तने का व्यास 30

मीटर से भी अधिक हो सकता है। यह पेड़ न केवल 5,000 साल से अधिक समय तक जीवित रहता है बल्कि यह अपने जीवनकाल में 1,20,000 लीटर तक पानी भी जमा कर सकता है। भूमिगत जल स्तर बढ़ाने में इस पेड़ की महती भूमिका है। आप भी कभी मांडू जाये तो इसे एक बार अलग नजर से देखे। मांडू में ऐसे कई वृक्ष मिल जायेंगे। □

युवा टीम को ये भी यकीन भी है कि जमीनी चुनौतियों के मुकाबले पानी, पेड़ के संरक्षण और गोवंश संवर्धन के मौजूदा काम इतने बड़े हैं कि किसी दिन प्रधानमंत्री की जुबान पर हमारे गांव का जिक्र जरूर होगा। घूँघट की आड़ से मारवाड़ी में बतियाती और 'राबोड़ी' और 'कैर-सांगरी' की सब्जी परोसती महिलाएं याद दिलाना नहीं भूलतीं कि 'धे' म्हारी बातां ने बड़ा लोगों तक पहुँचाजे, पानी रो दुख दूर होवै'। अब जिम्मा हमारा है कि भरपूर मेहमान नवाजी वाले गांव के पानीदार काम की बात तो दूर तक पहुँचाया जाए साथ ही गांव की जरूरत यानी 'बांध' की सुनवाई भी जल्द हो

## ‘अमृत उत्सव’ मनाता गाँव ‘नादिया कला’



डॉ. खिप्रा माथुर

(लेखक - दो दशक से पत्रकारिता और पत्रकारिता में कैपेन एडिटर, अमेरिका के ग्लोबल स्टेट व्यू अग्रब्रार की कंसल्टिंग एडिटर।)

मारवाड़ का इलाका यानी भारत और राजस्थान दोनों का पश्चिमी छोर। थार मरूस्थल वाले इन सरहदी शहरों का मिजाज एकदम देसी है और यही खूबी देशी विदेशी सैलानियों को यहां खींच लाती है। बेहद तपिश के लिए तो ये मशहूर हैं ही क्योंकि सूरज पूरे साल सबसे ज्यादा आग यहीं उगलता है। रंग बिरंगी संस्कृति से भरीपूरी बस्तियों में कुछ रंग अगर फीके हैं, कुछ तड़प है तो वो सिर्फ पानी की खातिर। इतिहास की जिन गाथाओं को जानने के लिए किलों, स्मारकों, मन्दिरों, संग्रहालयों का दौरा करने हम यहां कदम रखते हैं, दाल, बाटी, चूरमे का स्वाद चढ़ाए और लोक

गायकी को मन में बसाए हुए लौट भी आते हैं मगर यहां सुदूर बसे गांवों की प्यास से हम वाकिफ नहीं हो पाते। अच्छी सड़कों की वजह गांवों तक पहुंचना आसान तो हो गया है मगर पानी जैसे संसाधनों के बगैर इस पहुंच को ना तरक्की में तब्दील किया जा सकता है ना ही ग्रामीण-पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। गांव की पंचायतों में बनाई जल-समितियां क्या कर पा रही हैं और कितनी असरदार हैं ये अभी मुख्यधारा की बहस का हिस्सा नहीं। यही वजह है कि पानी की बेहद फिक्र के बावजूद गांवों की गुहार अनसुनी ही है।

**75 अमृत धेरे, दर्जन भर तालाब, हजारों पेड़**

जोधपुर से करीब 70 किलोमीटर अन्दर जाते हुए बावड़ी पंचायत समिति के मोड़ से दिखाई दिया सांझ से गले मिलता हुआ गांव 'नादिया कला'। सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ छांव का इन्तजाम किए हुए और बसावट

शुरू होते ही एकदम साफ सुथरे इस गांव की युवा टीम सरपंच जसवंत सिंह भाटी के घर की बैठक में डेरा डाले हुए मिली। बात छिड़ी गांव के विकास और जल के काम की तो साल 2008 में महाराणा प्रताप यूथ क्लब बनाकर साथ आए युवाओं की सोच और सक्रियता का आभास हुआ। जोधपुर शहर में अपने व्यवसाय करने वाले प्रकाश सोनी और गांव में ही अपना काम कर रहे बाबूलाल सिंघवी पूरे गांव के दो दिन के दौरों में साथ रहते हुए बताते हैं कि महाराणा प्रताप युवा मण्डल के सक्रिय साथियों में गणपत राम मेघवाल, तुलछ पूरी गोस्वामी के अलावा भरत सिंह, शेर सिंह, कानसिंह, रातूराम, श्याम सेन, दयाल सिंह शामिल हैं। इस मंडली के सक्रिय सदस्य जसवंत तो अब सरपंच हैं ही, जिनके साथ मिलकर पूरी टीम ने पिछले चार सालों में जल-स्रोतों के संरक्षण, वृक्षारोपण और वाटिकाएं बनाने के साथ ही गोपाल गौशाला में

पशुओं के लिए पानी के काम हाथ में लिए हैं। गांव में बड़ और पीपल के पेड़ लगाने और ताल-नाड़ियों की खुदाई के लिए जंगली बबूलों की कटाई सबसे भारी काम है। प्रदेश भर में ही ये बबूल तालाबों की खुदाई, खेती, गोचर विकास जैसे हर काम में अड़चन हैं। बबूल की झाड़ियों को काटने, मिट्टी की खुदाई और समुदाय के हर काम में गाँव के बुजुर्ग, युवा और महिलाएं सब साथ जुटते हैं।

जात-पात से परे इस समरस और आस्थावान गांव की ऊर्जा से भरी टीम बताती है कि जेठ माह की भरी गर्मी में पौधारोपण का काम शुरू किया तो दिन चढ़ते-चढ़ते सब पसीने में तर हो गए और काम पूरा होते होते अचानक बारिश होने लगी। लगा जैसे कुदरत ने अपना आशीर्वाद हम पर बरसा दिया। यूं चार सालों में पूरे गांव में करीब छह हजार पौधे रोपकर एक-एक की सार संभाल की गई है। महाराणा प्रताप वाटिका, भीमराव अम्बेडकर वाटिका, नारायण वाटिका सहित अब तक छह वाटिकाओं यानी नर्सरी तैयार करना आसान काम कतई नहीं क्योंकि पानी की किल्लत के बीच इन्हें जिन्दा रखना मुश्किल काम है। इसीलिए वाटिकाओं में भी भामाशाहों यानी दानदाताओं की मदद लेकर टांके बनाए हैं ताकि पौधों को पानी आसानी से पिलाया जा सके। स्थानीय जड़ी बूटियों और औषधीय गुण वाले पौधों के लिए खास तौर से धन्वतरी वाटिका भी बनाई गई है जिसके लिए जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने मार्गदर्शन दिया। शुष्क



जात-पात से परे इस समरस और आस्थावान गांव की ऊर्जा से भरी टीम बताती है कि जेठ माह की भरी गर्मी में पौधारोपण का काम शुरू किया तो दिन चढ़ते-चढ़ते सब पसीने में तर हो गए और काम पूरा होते होते अचानक बारिश होने लगी। लगा जैसे कुदरत ने अपना आशीर्वाद हम पर बरसा दिया। यूं चार सालों में पूरे गांव में करीब छह हजार पौधे रोपकर एक-एक की सार संभाल की गई है।

इलाकों में वनस्पतियों और पारिस्थितिकी पर शोध के लिए बने 'काजरी' जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों की टीम ने यहां दौरा कर पर्यावरण और आजीविका के सुझाव दिए हैं लेकिन असल काम खेती, पानी और मिट्टी की जुगलबन्दी का है। बाजरा, मोठ, ज्वार, जीरा, मोठ, प्याज सहित हर मौसम का अनाज और हर मौसम की सब्जियां होती हैं यहां मगर पानी अब भी 600-700 फीट नीचे ही है इसलिए न खेती करना आसान है ना आजीविका चलाना।

फिलहाल जो बात सबके समझ में बैठी है कि बड़े बदलाव और

पानी के तौर के लिए पहले पेड़ों की घनी आबादी चाहिए। इसके लिए पौध और ट्री गार्ड का इन्तजाम कुछ संस्थाएं कर देती हैं लेकिन युवाओं ने स्थानीय तौर पर जाली से बने ट्री-गार्ड बनाकर खुद किफायत करना सीख लिया है। पौधों को सुरक्षा देते ईंटों के घेरों पर हरा, सफेद, केसरिया पोतकर 'आजादी का अमृत उत्सव' मनाने की तैयारी में गांव अभी से जुट गया है। पूरे 75 घेरे तैयार करने के संकल्प के साथ ही चार नए तालाब और खोद दिए हैं। करीब 7-8 तालाबों को गहरे करने का काम पूरा हुआ है। गांव वाले खुद ही जेसीबी से खुदाई और डीजल के लिए करीब 5 लाख रूपए का

सहयोग कर चुके हैं। हजारों ट्रॉली मिट्टी बाहर निकाली गई। कुछ ट्रैक्टर मालिक तो निस्वार्थ ही करीब डेढ़ महीने तक इस काम में जुटे रहे। हाल ही यहां के सबसे पुराने कल्याण सागर का गहरीकरण हुआ है और इस तालाब की पाल पर वृक्षारोपण के लिए इंटों के घेरे भी तैयार हैं। साथ ही चार नाड़ियों का काम अभी जारी है। दुनिया भर में साल 2030 तक हासिल किए जाने वाले जिस टिकाऊ विकास लक्ष्य की बात बड़े मंचों पर की जा रही है उनमें 'नादिया कला' जैसे जमीनी काम और कुदरत के साथ तालमेल वाले जीवन की बात ही ज्यादा सुनाई देनी चाहिए। संसाधनों का पूरा दोहन कर विकास की दौड़ में आगे पहुँचे देश अब आर्थिक साम्राज्यवाद की होड़ में हैं। ऐसे में भारत के गाँव ही हमारे टिकाव और विकास की धुरी बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं।

### मन्दिर-पहाड़ी-संन्यासी, 'बांध' की आस

ये पूरा गांव जल और वृक्षों को लेकर बेहद सजग है। पहाड़, रेत, आस्था, परंपरा, सौहार्द सब इसके हिस्से हैं। गांव की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी बन गए हैं और उनकी भागीदारी इन सब कामों में बढ़ चढ़कर है। बुजुर्गों की पारंपरिक समझ का भी युवा पूरा मान रखते हैं। कुछ साल पहले तक ही जंगली बबूल और सुनसान रास्तों से आना जाना अखरता था। खुले में जंगली जानवरों का खतरा भी रहता था। अब पानी और वृक्षारोपण के काम से जैसे पूरे इलाके में सुकून सा पसर गया

है। दूसरी तरफ मनरेगा में शुरू हुए कुछ काम ऐसे हैं जैसे गड्डों में बहता पैसा। गांव के एक हिस्से में मनरेगा में खुद रही नाड़ी का काम बरसों बरस में भी पूरा नहीं हो पाया है। सरकारी अक्षमता का ये जीवंत उदाहरण है। वहीं समुदाय की भागीदारी और निगरानी में हुए काम असल भी हैं, समयबद्ध और किफायती भी।

गांव में ऊंची पहाड़ी पर लोकदेवता गोसाईं जी का मन्दिर है जहां हर साल मेला भरता है। वहीं रास्ते में एक गुफा भी है जिसे यहां गुजर बसर कर रहे एक संन्यासी प्रेमसुख महाराज ने अपने हाथों से खोदा है। गुफा में जीवन बिताते हुए, पहाड़ों के बीच एक एनिकट बनकर उन्होंने जल-संरक्षण की अद्भुत मिसाल पेश की है। यही हमारी सनातन परंपरा की संपदा है, जिसकी संभाल गाँव के सरल मन के ही बूते का रह गया है। इस मन्दिर के पीछे की ओर पुराने समय का टांका भी बना हुआ है जहां बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। वहीं नजदीक नाड़ी की खुदाई का काम भी मनरेगा में हुआ था। इस काम को ठीक के अंजाम देने के लिए सरपंच जसवंत ने गांववासियों से पूरे सौ दिन लग कर काम करवाया ताकि सरकारी मशीनरी के बूते हो रहे पानी के काम में कोई कोताही न बरते। मगर बाकी के तमाम काम समुदाय और संस्थाओं की मदद से ही आगे बढ़ रहे हैं। समस्त महाजन संस्था, ग्राविस और सूर्या फाउण्डेशन जैसी संस्थाएं जरूरत के मुताबिक काम में भरपूर सहयोग कर रहे हैं।

अपनी संस्कृति और इतिहास से करीबी पहचान रखने वाले युवा बताते हैं कि अरावली पर्वतमालाओं के आलिंजन में फैले इस इलाके में ही जोधपुर के मशहूर और बेहद कलात्मक किले मेहरानगढ़ की नींव रखी गई थी। लेकिन वो नींव बार-बार ढह जाती थी, और इसीलिए यहां से मीलों दूर शहर के बीचों बीच ये किला बनाया गया। उबड़ खाबड़ पथरों के बीच बसे गांव के इस मन्दिर से पूरे गांव का खूबसूरत नजारा दिखाते हुए सरपंच जसवंत और उनके साथी ये बात बेहिचक कहते हैं कि हर साल जब पानी बरसता है तो उसे व्यर्थ बहता देखकर दिल दुखता है।

कुदरत भरपूर देती है और अगर सारा सहेज लिया जाए तो वो इतना है कि इस गांव का ही नहीं आस-पास के 8-10 गांवों की प्यास भी बुझ जाए। बल्कि जमीन पूरी तर हो जाए, इतना। यहां की करीब 11 हजार बीघा खाली जमीन है जिसका इस्तेमाल पानी को बांधने के लिए किया जा सकता है। पहाड़ों से बहते पानी को बांधने के लिए पूरी योजना तैयार है, जमाबन्दी, नक्शा और ड्रोन की मदद से सरकारी नाप जोख का काम भी कुछ हुआ है। फाइलें अटकी ना रहें और बांध का काम जल्द शुरू हो जाए तो यहां नहरी पानी की जरूरत ही नहीं।

### 'राबोड़ी' - 'कैर सांगरी' की मनुहार

गांव में ठहर कर किसी युवा, महिला या बुजुर्ग से पूछेंगे तो हर जवान से पानी की समस्या का ही जिक्र मिलेगा।

जो पानी है वो भी खारा इसीलिए पीने के लिए तो हर घर को टैंकर ही मंगवाना पड़ता है। करीब 500-600 रूपए की कीमत में आने वाले चार-पांच टैंकरों के बगैर किसी आम परिवार का गुजारा नहीं। जीने की मूल सुविधाओं से जूझ रहे इस गांव के खुले इलाके में दूर दूर तक सोलर प्लांट लगे हैं। गांव वासियों को इस बात की शिकायत भी है कि पश्चिम के गांवों में कम्पनियों को मुनाफा तो खूब नजर आता है लेकिन गांव के विकास और आजीविका से उनका कोई वास्ता नहीं।

देश के जल-शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मारवाड़ के ही हैं,

इसीलिए गांव वालों की आस भी उनसे ज्यादा है। युवा टीम पूरे भरोसे के साथ कहती है कि उन तक बस बात पहुंचने की देर है, पीने के पानी का इन्तजाम भी होगा और बांध बनाने का काम भी जरूर आगे बढ़ जाएगा। ये काम आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदलने वाला है इसलिए युवा पीढ़ी किसी भी कीमत पर इन कामों से समझौता नहीं करती।

उन्हें मालूम है कि गाँव की खूबसूरती, खुशबू, स्वाद, स्वागत-सत्कार और प्रेम-प्यार की बोली के पीछे लोग खिंचे चले आएंगे लेकिन सबसे कीमती संसाधन तो पानी ही है। युवा टीम

के साथी प्रकाश का ये भी यकीन भी बड़ा है कि जमीनी चुनौतियों के मुकाबले पानी, पेड़ के संरक्षण और गोवंश संवर्द्धन के मौजूदा काम इतने बड़े हैं कि किसी दिन प्रधानमंत्री की जुबान पर हमारे गांव का जिक्र जरूर होगा। घूँघट की आड़ से मारवाड़ी में बतियाती और 'राबोड़ी' और 'कैर-सांगरी' की सब्जी परोसती महिलाएं याद दिलाना नहीं भूलतीं कि - 'थे म्हारी बातां ने बड़ा लोगां तक पहुँचाजे, पानी रो दुख दूर होवै। अब जिम्मा हमारा है कि भरपूर मेहमान नवाजी वाले गांव के पानीदार काम की बात तो दूर तक जाए ही गांव की जरूरत यानी 'बांध' की सुनवाई भी जल्द हो। □

## जल विज्ञान में नवाचार के लिए प्रदेश को मिला भारत सरकार का एक्सीलेंस अवॉर्ड

### जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने दी बधाई



जल विज्ञान में नवाचार के लिए प्रदेश को भारत सरकार का एक्सीलेंस अवॉर्ड प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली में 9 एवं 10 जनवरी 2024 को आयोजित जल विज्ञान परियोजना की राष्ट्र स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी ने जल विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार के लिए प्रदेश का चयन किया गया। सचिव जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार श्रीमती देवाश्री मुखर्जी ने परियोजना संचालक, जलसंसाधन विभाग श्री आर के गुप्ता को एक्सीलेंस अवॉर्ड प्रदान किया। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम

सिलावट ने विभाग के अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये बधाई दी। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक सहायता प्राप्त जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय जल सूचना केंद्र (SWIC) की स्थापना कर सतही एवम भूजल के आंकड़ों के एकीकरण, प्रसार के साथ विश्लेषणात्मक सूचना तंत्र विकसित किया जा रहा है। □

# हम अपनी पीढ़ियों को क्या स्वच्छ वातावरण दे पायेंगे



अरुणमोह सिंघ छाँकर

(लेखक - नर्मदा समग्र  
कार्यकर्ता।)

नदियाँ न पीए कभी अपना जल,  
वृक्ष न खाए कभी अपना फल।

ये पंक्तियाँ हमें यह बताती हैं कि अगर नदियाँ अपना जल नहीं पीती तो कौन पीता है। वृक्ष अपने फल नहीं खाते तो फल कौन खाता है। इनका उत्तर है। 'मानव', मानव प्रकृति से वह सब लेता है। जिसकी उसे आवश्यकता है। लेकिन वह प्रकृति को क्या देता है। वह नदियों को प्रदूषित करता है। वह उन वृक्षों को काटता है जो उसे ऑक्सीजन देते हैं। जीवन देते हैं।

आज हमारे देश की नदियाँ प्रदूषित हैं। जिन नदियों को पानी से मानव की प्यास बुझती है। खेतों की सिंचाई होती है। उन्हीं नदियों को आज मानव प्रदूषित करने पर आतुर है। क्या हम कभी यह सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, क्या उन्हें शुद्ध वातावरण मिल पाएगा, क्या उन्हें शुद्ध पानी मिल पाएगा, क्या उन्हें शुद्ध वायु के लिए वृक्ष मिल पाएंगे। हम विकास के नाम पर हजारों

वृक्ष काट देते हैं। विकास के नाम पर हमारी नदियों में कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित और जहरीले केमिकल मिला देते हैं। शहरों से निकलने वाले गंदे नाले नदियों में आकर मिलते हैं। लेकिन हमें इन चीजों पर सोचने का समय नहीं है। आज हमारे देश में छोटी-छोटी नदियाँ तो नाले में तब्दील हो गई हैं और इस प्रदूषण का प्रभाव केवल मानव जाति तक सीमित नहीं है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पशु पक्षियों और जानवरों पर पड़ा है। आज बहुत सारे पशु-पक्षी और जानवर विलुप्ति की कगार पर हैं। लेकिन हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। नदियों को हमारी आवश्यकता नहीं है। हमें नदियों की आवश्यकता है। उसी प्रकार पर्यावरण को हमारी आवश्यकता नहीं है। हमें पर्यावरण की आवश्यकता है।

आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है लगातार बढ़ती वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। अगर हम इसी प्रकार वृक्षों को काटते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि वृक्ष पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। कभी सोचा है कि फिर क्या होगा। क्या पृथ्वी पर जीवन संभव होगा। अगर हम ऐसे ही नदियों को

प्रदूषित करते रहे तो क्या हम पानी के बिना जीवन की कल्पना भी कर सकते हैं। आज हमें सोचना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसा वातावरण सौंपेंगे और हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण नदियों के बारे में जागरूक करें जो गलतियाँ हमसे हुई हैं। हमारा कर्तव्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी यह गलती न दोहराये। ग्लोबल वार्मिंग का समाधान यह हमारे लिए या जलवायु परिवर्तन चुनौतीपूर्ण हो सकता है लेकिन यह असंभव नहीं है। जब संयुक्त प्रयास किए जाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो या जलवायु परिवर्तन इसे रोका जा सकता है। बस आवश्यकता है जागरूकता की।

हमें स्वयं भी जागरूक रहना है और सभी को जागरूक करना है जो लोग नदियों एवं वृक्षों का महत्व नहीं जानते हैं। हमें उन्हें इनके महत्व के बारे में समझाना है। नदियाँ हमारा वर्तमान भी हैं और वे हमारा भविष्य भी हैं। नदियों के प्रदूषित होने से न केवल जलीय जीवों का बल्कि हमारा जीवन भी संकट में पड़ सकता है। नदियाँ हमारी जीवन रेखा की तरह हैं, नदियाँ हमें जीवन देती हैं। उनके बिना मानव जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। आइए हम मिलकर नदियों और वृक्षों को संरक्षित करने की दिशा में कदम उठाएँ। □

# स्वामी सदाचैतन्य ब्रम्हचारी (सादा बाबा) एक अनोखे शिव भक्त



लालाराम यकर्वती

(लेखक - परिक्रमा ग्रायाम  
समन्वयक, नर्मदा समग्र  
ब्यास भोपाल।)

मां नर्मदा का पूरा क्षेत्र तपोभूमि हैं और मां गंगा का किनारा सिद्धभूमि कहलाती हैं। मां नर्मदा के सम्पूर्ण क्षेत्र में एक से बढ़कर एक तपोनिष्ठ संत गुप्तरूप और प्रत्यक्षरूप से विराजमान हैं। मां नर्मदा के दोनों तट संतो से और सिद्धों से ऐसे भरे हैं कि जगह तिल रखने को भी खाली नहीं हैं, प्रत्येक जगह पर किसी न किसी संत ने तपस्या किया है। मां नर्मदा जी के किनारे श्रद्धालुजन भारत के कोने-कोने से तो आते ही हैं, साथ ही विदेशों से भी मां के किनारे खिचें चले आते हैं। ऐसे ही एक संत थे स्वामी सदाचैतन्य ब्रम्हचारी जी (सादा बाबा)। सादा बाबा भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे, जब से मां नर्मदा के तट पर आये और यहीं के होकर रह गये।

सादा चैतन्य ब्रम्हचारी जी का शरीर पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिला का था। बचपन से ही भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, अतः शिव जी के अनेकों स्रोत उन्होंने बचपन में ही कंठस्थ कर लिया था। शिक्षा-दीक्षा के बाद अनेक कम्पनियों में काम करते हुये, बीच-बीच में उत्तराखंड और हिमालय की पहाडियों में भगवान भोलेनाथ की साधना के लिये जाया करते थे। कॉलेज की पढाई के समय ही इनको कहीं से श्री शैलेन्द्र नारायण घोषाल जी की तपोभूमि नर्मदा नामक बंगाली भाषा की किताब का एक खंड प्राप्त हुआ, उस प्रथम खंड को पढते हुये सादा बाबा जी को ऐसा रस आया कि 300-400 पेज की किताब मात्र 2 दिन में पढकर, किताब के अगले खंड तलाश शुरू कर देते। तपोभूमि नर्मदा किताब ही सादा बाबा के जीवन में नर्मदा जी जानकारी देने का माध्यम बनी। तपोभूमि नर्मदा किताब के सभी खंडो को बार-बार पढते रहते और भगवान



शिव से प्रार्थना करते के प्रभु मुझे भी आपकी प्रिय मैकलसुता के किनारे जाने की अनुकूलता बनायें। कम्पनियों में काम करने के दौरान उनका मन उच्चाटन हो जाने से उन्होने नौकरी को छोडकर हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ-साथ नर्मदा जी के किनारे भी समय व्यतीत करने लगे। ऋषिकेश में भ्रमण के दौरान सादा बाबा की भेंट अखंड बाबा जी (काका गुरु) से हुई। अखंड बाबा जी के व्यवहार से प्रभावित होकर उन्होने गुरुदीक्षा के लिये मार्गदर्शन लिया, तब अखंड बाबा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें अभी गुरुदीक्षा के लिये अभी अधिकार नहीं मिला है, अतः वे अपने बडे गुरुभाई स्वामी अच्युत चैतन्य जी महाराज, साधन संघ आश्रम, ऋषिकेश (हरिद्वार) से गुरुदीक्षा लेने का कहां। सादा बाबा कुछदिन स्वामी अच्युत चैतन्य जी महाराज की सेवा में रहकर दीक्षा ग्रहण की, तत्पश्चात पतित पावनी मां नर्मदा की पद प्रदक्षिणा की आज्ञा मांगी, गुरुदेव ने कहां मेरी ओर से आज्ञा तो है किन्तु जिसकी प्रदक्षिणा करनी है, उसकी कृपा जरूरी है। उसके बाद सादा बाबा नर्मदापुरम स्थित सेठानी घाट के ठीक सामने जोशीपुर हनुमान मंदिर आश्रम में कई दिन रुके, साथ ही कुछ समय ओम्कारेश्वर के एकांतिक स्थलों में कुटिया बनाकर नर्मदा

मैया से प्रदक्षिणा की अनुमति मांगी। वर्ष 2011 में नर्मदा मैया की कृपा से सादा बाबा जी ने उद्गम कुण्ड अमरकंटक से नंगे पांव, पैदल प्रदक्षिणा आरंभ की। मां नर्मदा प्रदक्षिणा की प्रथम जानकारी तपोभूमि नर्मदा पुस्तक से मिली थी। अतः इस किताब में बताये गये स्थलों में महाराज जी जरूर रूकते थे। सादा बाबा हमेशा अकेले और नर्मदा मैया के किनारे मार्ग पर ही चलते, जहां उन्हें अच्छा लगता वहीं पर आसन लगाते थे। अमरकंटक से चलकर जब वे डिंडौरी आये तो उन्होंने नगर के सिविल लाइन स्थित सिद्ध टेकरी में कुछ दिन आसन लगाया, उसी दौरान उन्होंने श्री हरि त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, सिविल लाइन में स्थित भोलेनाथ के प्रथम बार दर्शन किये। पूरी परिक्रमा के दौरान उन्होंने अनेकों शिव मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन किये परन्तु सिविल लाइन डिंडौरी स्थित शिव जी ने इन्हें ऐसा पकड़ा कि सादा बाबा यहीं के होकर रह गये। अंत समय में जब सादा बाबा अल्मोडा-उत्तराखंड में थे, वहां से श्री हरि त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, सिविल लाइन डिंडौरी खिंचे चले आये। स्वामी सदाचैतन्य ब्रम्हचारी जी सादा बाबा का पांच भौतिक शरीर यहीं पर भोलेनाथ के सम्मुख पंचतत्व में विलीन हुआ।

वर्ष 2011 को अमगवां जिला मंडला स्थित सुमनपुरी माताजी के आश्रम में मां तारादेवी मंदिर के भूमिपूजन कार्यक्रम हेतु नर्मदा समग्र से प्रबंधक श्री अशोक पाटीदार सर, जबलपुर संभाग के समंवयक श्री रामगोपाल पाटीदार और मैं आश्रम पहुंचे। यही पर पद् प्रदक्षिणा करते हुये स्वामी सदाचैतन्य ब्रम्हचारी जी सादा बाबा अलग से कुटिया बनाकर रूके थे। सादा बाबा का नर्मदा समग्र के कार्यकर्ताओं से प्रथम परिचय श्री अशोक पाटीदार ने यहीं पर कराया। उसके बाद सादा बाबा जबलपुर, नरसिंहपुर होते हुये नर्मदापुरम जिले के पहले घाट पांसीघाट में पहुंचे, उसी समय संयोग से मैं भी वहां के प्रवास पर था, अतः दूसरी भेंट पांसीघाट-उमरदा जिला नर्मदापुरम में हुई। दूसरी भेंट के समय महाराज जी ने चातुर्मास करने हेतु उपयुक्त स्थान की जानकारी मुझसे ली। सादा बाबा की प्रदक्षिणा का प्रथम चातुर्मास नर्मदापुरम शहर से 6 किमी. की दूरी पर स्थित गोदरी घाट मालाखेडी में हुआ। यहां पर चातुर्मास के दौरान अशोक पाटीदार सर, उमाशंकर चौबे जी

और नर्मदा समग्र के अनेक कार्यकर्ताओं को सर्वप्रथम तपोभूमि नर्मदा पुस्तक की जानकारी महाराज जी ने दी। हम सभी को नर्मदा समग्र के कार्यों को किस तरह अच्छे से करें, इस हेतु अनेकों सुझाव और मार्गदर्शन दिया।

प्रदक्षिणा करते हुये द्वितीय चातुर्मास खरगोन जिले में मां नर्मदा जी के उत्तर तट पर भामपुरा गांव के बाहर स्थित एकांत कुटिया में किया। द्वितीय चातुर्मास के दौरान मालवा-निमाड भाग के समंवयक श्री मनोज जोशी जी और श्री भरत बैरागी जी का प्रथम संपर्क हुआ। चातुर्मास के दौरान इन लोगों महाराज जी के सान्निध्य में अनेक अच्छी अनुभूतियां भी हुईं। तृतीय चातुर्मास डिंडौरी जिले के उत्तर तट पर स्थित लुकामपुर गांव में हुआ, इस दौरान डिंडौरी नगर में निवासरत श्री रवि बर्मन सर, श्री अनुराग बिलैया, श्री रामानंद झा और अनेकों गणमान्य लोगों के साथ प्रथम भेंट हुई। इसी चातुर्मास के दौरान नर्मदा समग्र के संस्थापक श्री अनिल माधव दवे जी उनसे भेंट करने यहां पर पधारे थे।

वर्ष 2015 में सादा बाबा की प्रदक्षिणा 3 साल, 3 महीने और 13 दिनों बाद उद्गम कुण्ड अमरकंटक में समापन तत्पश्चात ओम्कारेश्वर में जल अर्पण कर भंडारा हुआ। उसके बाद वे सिविल लाईन डिंडौरी स्थित श्री हरि त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में आकर आसन लगाया। जीर्ण-शीर्ण पड़े शिव मंदिर के जीर्णोद्धार की योजना बनाई और कार्य शुरू किया, महाराज जी के मार्गदर्शन और अथक प्रयास से ही श्री हरि त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 2018 में संभव हो सका।

सादा बाबा जी ने अपने जीवन पर्यन्त नर्मदा समग्र के कार्यकर्ताओं का बड़े ही श्रद्धाभाव से आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया एवं बताया कि अपने जीवन में प्राचीन धार्मिक का क्या महत्व है। उन्होंने हमेशा ही नर्मदा समग्र के कार्यों में अपनी सहभागिता की है। ऐसे पूज्य शिव भक्त संत बहुत ही बिरले मिलते हैं। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुये लिखना सूर्य को ज्योति दिखाने जैसा है, परन्तु उनके परम स्नेही आषीष और मां नर्मदा की कृपा से उनके बारे में लिख सका। यह लिख पाना मेरी सार्मथ्य नहीं थीं। □

# नाम से ही नहीं कर्म से सादे थे सादा बाबा



मनोज ज़ोशी

(लेखक - मुख्य सम्बन्धक,  
नर्मदा समग्र व्यास गोपाल।)

कहते हैं नर्मदा के पथ पर सिद्ध संत का सानिध्य बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। मैं जैसे तो माँ नर्मदा के किनारे से दूर का निवासी हूँ। माँ नर्मदा जी की सेवा से मुझे जोड़ने वाले ब्रह्मलीन श्री अनिल माधव जी दवे रहे। नर्मदा समग्र की गतिविधियों के माध्यम से माँ नर्मदा के किनारे प्रवास करने का अवसर प्राप्त हुआ दवे जी भाई साहब कहते थे नर्मदा जी का पथ हो और संत एवं परिक्रमावासी का सानिध्य प्राप्त न हो तो हमारा प्रवास अधुरा है।

नर्मदा समग्र में मालवा निमाड़ भाग के समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए प्रवास पर एक दिन मोबाइल की घंटी बजी तत्कालीन नर्मदा समग्र के प्रबंधक श्री अशोक जी पाटीदार ने नर्मदा समग्र के कार्यों के संबंध में बात करते हुए सहज भाव से कहा कि हमारे कार्य प्रभावित न होते हुए परिक्रमावासी एक संत के चार्तुमास की व्यवस्था करनी है। नर्मदा पथ पर संत की व्यवस्था करने का दायित्व मन प्रफुल्लित था। नर्मदा समग्र में साथी भाग समन्वयक भरत जी बैरागी से



संवाद कर हम संत जी से संपर्क की योजना बनाने लगे। मध्यप्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही दूरभाष के माध्यम से हम संत श्री सादा बाबा के संपर्क में रहे कोटेश्वर (निसरपुर) से चूँकि नर्मदा समग्र के प्रबंधक ने बोला था इसलिए हम संत श्री के लिए अच्छी से अच्छी जगह तलाशते और बताते लेकिन संत श्री हर स्थान का मना कर आगे बढ़ जाते भरत जी और मैं हैरान परेशान आखिर बाबा चाहते क्या है? अशोक जी से बात की उन्होंने कहा बाबा जहाँ कहे वहाँ आप लोग व्यवस्था जमा देना चलते-चलते ओ दिन आ ही गया बाबा ने भामपुरा में माँ नर्मदा किनारे बनी एक घास की झोपड़ी को चार्तुमास के लिए

चुना हम स्तब्ध थे छोटी से कुटिया ऊपर व्यवस्थित छत न नीचे व्यवस्थित फर्श फिर भी बाबा को जगह पसंद आ गई। पता किया कुटिया किसकी है। ग्राम के बंधु ने परिक्रमावासियों के लिए ही बनाई। उनसे पूछा सहज स्वीकृति मिलते ही बाबा ने वहाँ अपना आसन लगा दिया। आवश्यक पूर्तियों में हम जुट गये।

कुटिया व्यवस्थित कर हम निकल आये पास चल रहे माँ नर्मदा मंदिर के अन्न क्षेत्र में बाबा के भोजन की व्यवस्था की नियम और अनुशासन में सख्त बाबा ने अन्न क्षेत्र की व्यवस्थाओं को देखकर वहाँ भोजन करना त्याग दिया और उपवास करने लगे। गांव के माध्यम से हमें पता चला उसके उपरांत बाबा जी स्वयं अपना भोजना बनाकर पाने लगे। पुरा चार्तुमास बड़ी ही सादगी से माँ नर्मदा जी की साधना में लीन रहें।

मान्यता है कि संत की कृपा कर अनुभव करना चाहिए उसे वृतांत में परिवर्तित नहीं करना चाहिए ये सादा बाबा भी बार-बार कहते थे। आज जब वह स्थूल शरीर में नहीं है। मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति और मेरा 4 व्हीलर का सपना साकार ही बाबा के आशीर्वाद से पूर्ण हुआ। बाबा के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहूँगा कि वास्तव में वे अपने नाम के अनुरूप आचरण से भी सादा बाबा ही थे। □

# सादा बाबा से परिक्रमा के समय एक मुलाकात

मेरा जन्म नर्मदा के किनारे उत्तर तट में ग्राम सहजपुरी विकासखंड नारायणगंज जिला मंडला में हुआ हमारा परिवार साधु संतो एवं परिक्रमासी की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहा 1980 के समय बरगी डेम बनने के कारण हमारा परिवार गांव से विस्थापित हो कर मंडला नगर में रहने लगा हालांकि मंडला आने के बाद साधु संतो की सेवा से दूर तो हो गए परंतु सेवा तो परिवार के संस्कारों के कारण थी 'हमारा सौभाग्य है कि हमें नर्मदा तट के किनारे अनेकों साधु संतों की सेवा का अवसर मिला था जिसके कारण आश्रमों से लगाव रहा और आश्रमों में सेवा देने जाने का जब भी अवसर मिला निकल जाते थे, लगभग 10, 12 वर्ष पूर्व दक्षिण तट में स्थित आमगांव आश्रम में चल रहे हवन पूजन मंडारे के कार्यक्रम में शामिल हुआ था शाम का समय हो चला था इस समय एक संत आश्रम की तरफ चले आ रहे थे हमने अपने साथियों के साथ उनका आश्रम के अंदर आने के लिए आग्रह किया संत

जी सरलतापूर्वक हमारा आग्रह स्वीकार किया अंदर आते उसके पश्चात हमने आश्रम की सुमनपुरी माताजी से बाबाजी की मुलाकात कराई, माताजी ने उन्हें अपनी कुटिया में रोकने का आग्रह किया परंतु साधु उनकी कुटिया में ना रुककर उन्होंने कहा कि मैं आपके बगीचे में अलग से किसी स्थान पर आसन लगा लूंगा' आश्रम के बगीचे में तरपाल खींचकर उनके रहने योग्य स्थान बनाया जिसमें उन्होंने अपना आसन लगाया हम भी मंडारे के कार्यक्रम से निवृत्त होकर संत के साथ बैठे उसके साथ वातालाप के दौरान उन्होंने कहा इस स्थान में काफी सकारात्मक ऊर्जा है जिसके कारण मैं इस आश्रम की ओर खिंचा चला आया यह स्थान बहुत ही ऊर्जा से भरा पूरा है आप लोग यहां आकर सेवा करते रहे'

नर्मदा परिक्रमा के समय अनेकों स्थानों का शास्त्र द्वारा उल्लेखित प्रसंगों को चर्चा हुई साथ ही मंडला के आसपास जैसे महाराजपुर संगम,

राजराजेश्वरी मंदिर के प्राचीन कथाओं की जानकारी के विषय में बताया 'आगे जब आप महाराजपुर संगम पहुंचे तो हमें लोग मिलने आया करते थे ' आप मां नर्मदा के घाटों के किनारे हो रही गंदगी, प्रदूषण के विषय में अनेकों बार चर्चा करते थे कि जब तक समाज नहीं जागेगा तब तक घाटों को साफ नहीं किया जा सकता अतः स्वच्छता को धर्म से जोड़कर देखा जाता चाहिए मां नर्मदा का तट पूजा का स्थान है न की प्रदूषित करने का स्थान अनेकों बार घाट में गंदगी करने वालों के ऊपर सादा बाबा को डांटते हुए देखा है आप आध्यात्मिक ज्ञान के साथ सामाजिक ज्ञान की भी जानकारी रखते हैं मानव को कैसे सात्विक आहार, विचार रखना चाहिए इस विषय हमेशा चर्चा करते थे। □

- निलेश कटारे,

भाग समन्वयक, महाकौशल

## सादा बाबा के साथ बिताये कुछ समय का वृत्तांत

अक्सर आपके जीवन में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण समय घटित हो जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हुई होती है। बस ऐसा ही एक दाकया कहो या मेरे प्रारब्ध के लाम जो मुझे एक यात्रा के दौरान प्राप्त हुये। इस यात्रा में शामिल होने का माध्यम श्री मनोज जोशी जी एवं श्री भरत बैरागी जी रहे। सादा बाबा किन्ही विशेष कारणों से भोपाल प्रवासा पर आये हुये थे और अपने प्रवास के बाद वापस डिंडोरी जाना था और मैं भी इस यात्रा में भाग लेने के लिये तैयार हुआ था मुझे नहीं पता था कि सादा बाबा भी हमारे साथ चलने वाले है। प्रातः जब मैं गंतव्य स्थान पर पहुंचा तब प्रथम बार सादा बाबा के दर्शन हुये अपनी दैनिक दिनचर्या अनुसार पूजा पाठ में लीन थे कसा हुआ शरीर, समेटे हुये सर पर सफेद बालों का जुडा, आंखों



में तेज, चाल में फुर्ती से वह सभी कार्य को कर रहे थे। पूजा के बाद जब बाबा अल्पाहार के लिये बैठे तब मेरा परिचय करवाया चूँकि बाबा जी के साथ प्रथम बार बैठा था तो थोडा असहज था लेकिन उनका मेरे प्रति व्यवहार ने मुझे जल्द ही अपनी चर्चा में जोड लिया।

सहजता से चर्चा करते हुये यात्रा आरंभ

हुई और बातों ही बातों में अपने जीवन की अनसुनी बातों से यात्रा को रोचक बना दिया। आपका जन मानस के प्रति दृष्टिकोण धर्म के प्रति गंहरी आस्था और पर्यावरण के प्रति आपकी रूची ने निसंदेह आपको तत्व दर्शी बना दिया था। कैसे छत्र जीवन से अध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ता चला गया और कैसे आप ने वैरागी बनने का निर्णय लिया सब कुछ इस यात्रा में हुई चर्चा के अंश थे। आपके साथ बिताया हर पल जीवन पर्यंत स्मृति में रहेंगे। आपके वैचारिक भाव एवं कार्य सनातन धर्म के लिये मील का पत्थर साबित होंगे। इतने जल्द आपका चले जाना सनातन समाज के लिये एक अपूरणीय क्षति है। □

- नवीन बोडर्ये,

भाग समन्वयक, नर्मदापुरम

# कुसुम/कोसुम

CEYLON OAK/LAC TREE

**Schleichera oleosa**

**SAPINDACEAE - लीची परिवार**



**डॉ. सुदेश वाघमारे**

(लेखक - सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक,  
म.प्र. राज्य वनसेवा, नगरीय  
पौधारोपण, दन्व्यप्राणी, प्रबंधन,  
जलसंरक्षण और जैव विविधता में  
विशेषज्ञता तथा सुदीर्घ नैदानी अनुभव।  
संप्रति- स्वतंत्र लेखक।)



कुसुम एक वृहद आकार का, विशाल वितान वाला अपने पीली-गुलाबी-रक्तवर्णी नव पल्लवों के कारण शीघ्र ही पहचान में आ जाता है। यह अक्सर छोटी पहाड़ियों के नालों में जहाँ अच्छी मिट्टी एकत्रित हो जाती है वहाँ प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह भारत के उन चुनिन्दा वृक्षों में से है जो हजारों वर्षों से भारत की देशज प्रजाति हैं।

**छाल** - भूरी-सफेद जो अनियमित शल्कों के आकार में प्रायः वर्ष भर निकलती रहती है।

**पत्तियाँ** - लगभग डेढ़ फीट आकार की संयुक्त पत्ती है। पर्णकों के प्रायः तीन जोड़े होते हैं। ऊपर के पर्णक बड़े और नीचे के छोटे होते हैं। पर्णक वृन्तहीन और शीर्ष पर नुकीले होते हैं। यह इस वृक्ष को पहचानने का सर्वोत्तम तरीका है।

**पुष्प** - एक पेड़ पर नर और दूसरे पर मादा फूल आते हैं परन्तु अपवाद स्वरूप

द्विलिंगी भी आते हैं। फूल छोटे, पीले, गुच्छों में और मार्च-अप्रैल में पर्णपातन के साथ आते हैं।

**फल** - लम्बा, लीची के आकार का और सिरे पर नुकीला जाता है। एक बीजीय फल में बीज के ऊपर खट्-मिट्टा अम्लीय गूदा होता है। वनवासियों और चरवाहों का जुलाई-अगस्त के माह का सबसे प्रिय फल है।

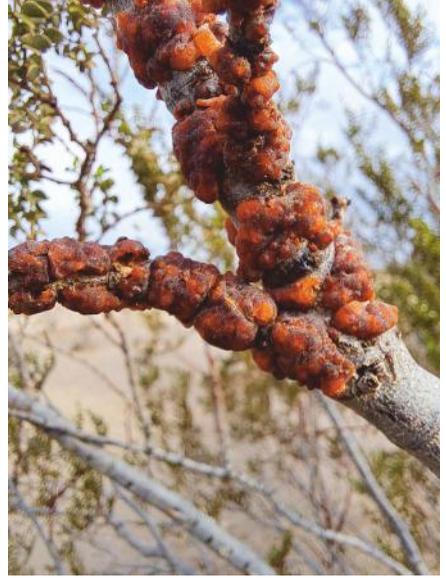
**उपयोग** - इसकी नई शाखाओं पर लाख के कीड़े पालकर व्यापारिक रूप से

लाख का उत्पादन किया जाता है। इसके बीजों से बहुउपयोगी तेल निकाला जाता है, जिससे पहले भोजन पकाया जाता था और चिमनिओं में जलाया जाता था। तेल त्वचा और गठिया-वात के रोगों के उपचार में भी काम आता है। पत्तियाँ बढ़िया पशु चारा हैं इसलिये बकरी पालने वाले इसकी शाखाओं को काटते हैं। लकड़ी बहुत मजबूत होती है जिसे किले और महल बनाने में उपयोग किया जाता था।

## खतरे के नजदीक (Near Threatened)

यह वृक्ष नर्मदा तट पर और उसकी सहायक नदियों पर यादृच्छिक पाया जाता है और इसके संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि यह IUCN की सूची में खतरे के नजदीक के रूप में दर्ज है। महाभारत में पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिये जो लाक्षागृह बनाया गया था वह इसी वृक्ष पर पाले गये कीट द्वारा निर्मित लाख से बना था। संस्कृत में इसे 'धनस्कंध' एवं लाक्ष वृक्ष के नाम से जाना जाता था। नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी के जंगलों में इसका अच्छा उत्पादन (लाख का) होता था जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। शासकीय निष्क्रियता और सही मार्केटिंग के अभाव में यह उपयोग समाप्त हो गया।

इसमें पाये जाने वाले प्रमुख रसायन बिटुलिन, लुपिऑन, बिटुलिनिक अम्ल एवं हाइड्रोसायनिक अम्ल हैं। □



### वार्षिक सदस्यता प्रपत्र

मैं ..... एक वर्ष के लिए नर्मदा समग्र त्रैमासिक पत्रिका की सदस्यता लेना चाहता/चाहती हूँ।

4 अंक - वार्षिक शुल्क 100 रुपये, (पोस्टल शुल्क सम्मिलित)

नाम : \_\_\_\_\_ लिंग : \_\_\_\_\_

कार्य : व्यवसाय  कृषि  नौकरी  विद्यार्थी  संगठन

संस्था : \_\_\_\_\_ दायित्व/पद : \_\_\_\_\_

फ़ोन : \_\_\_\_\_ मोबाइल : \_\_\_\_\_ ई-मेल : \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

जिला : \_\_\_\_\_ पिन कोड : \_\_\_\_\_ राज्य : \_\_\_\_\_

भुगतान विवरण : चेक/डिमांड ड्राफ्ट नं. : \_\_\_\_\_ दिनांक : \_\_\_\_\_ रुपये : \_\_\_\_\_

अदाकर्ता बैंक : \_\_\_\_\_ शाखा : \_\_\_\_\_

खाते की जानकारी (ऑन लाईन भुगतान हेतु)

Narmada Samagra  
State Bank of India  
Shivaji Nagar Branch, Bhopal, M.P.  
Ac no. 30304495111  
IFSC: SBIN0005798

दिनांक : \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

"नदी का घर"

सीनियर एमआईजी -2, अंकुर कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश - 462016  
दूरभाष + 91-755-2460754 ई-मेल : narmada.media@gmail.com

# नदी एम्बुलेस पर नन्हें बालक सुरेश का उपचार



राजेश जादव

(लेखक - नदी एम्बुलेस समन्वयक, नर्मदा समग्र व्यास I)

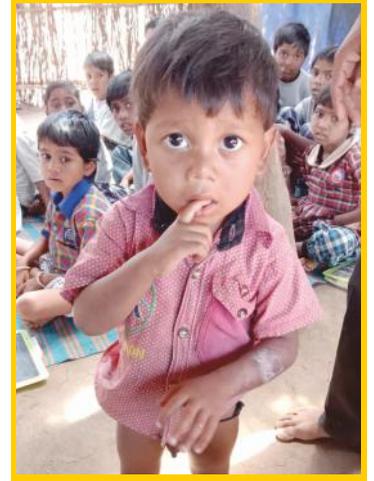
रोग :- बर्न ( गरम पानी से जला )  
नाम :- सुरेश पिता गिलदार  
उम्र :- 3 वर्ष  
स्थान :- सादरी तालुका धड़गांव जिल्हा  
नंदुरबार महाराष्ट्र  
उपचार :- दिनांक 27/02/21 को

10 दिन पहले इस बालक के हाथ में गर्म पानी गिर गया था और हाथ पूरी तरह से जल गया था नदी एम्बुलेस में बालक की मां बालक को दिनांक 27/02/21 को लेकर उपचार के लिए लाई थी, बालक का हाथ 40% जल गया था बालक को नदी एम्बुलेस में डॉ. कमलेश भावसार के द्वारा इलेक्ट्रो होमिओपैथी की दवाइयां द्वारा उपचार किया गया, उपचार के 10 दिनों बाद बालक का हाथ 90% ठीक हो गया। उपचार जारी है आगामी 1 सप्ताह के लिए।

नर्मदा समग्र न्यास द्वारा सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में संचालित नदी एम्बुलेस कार्य क्षेत्र यह क्षेत्र लगभग 100 कि.मी. से भी ज्यादा में फैला हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश का अलिराजपुर, धार व बड़वानी; महाराष्ट्र का नंदुरबार



उपचार के लिए लाया गया बालक



उपचार के बाद बालक



और गुजरात का छोटा उदयपुर जिले आते हैं। इस क्षेत्र में नर्मदा जी के किनारे रहने वाले लोगों तक पहुँचने या उन्हें किसी बड़े गाँव अन्य स्थान तक आने के लिए १ या २ स्थानों/ग्रामों में ही सड़क पहुँच मार्ग उपलब्ध है। इन वनवासियों के लिए नदी ही एक सुलभ मार्ग है। क्योंकि इन्हें किसी ग्राम या स्थान पर

आने-जाने हेतु 15-20 कि.मी. की दूरी पहाड़ियों से होते हुए तय करना पड़ती है। नर्मदा जी के किनारे दोनों तरफ विन्ध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ हैं।

ऐसे दुर्गम क्षेत्र में लोगों को सामान्य चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य नर्मदा समग्र विगत 14 वर्षों से सतत कर रहा है। □

## पर्यावरण पंचकोसी यात्रा - महाकौशल भाग



महाकौशल भाग में वर्ष 2023-2024 में जल एवं पर्यावरण संरक्षण, संबर्धन के लिए पर्यावरण पंचकोसी यात्रा का आयोजन किया गया हालाकि यह यात्राए प्रति वर्ष घाट टोलियों द्वारा कि जाता है जिसमे घाट टोली पर्यावरण पंचकोसी यात्रा निकलती है। पंचकोसी यात्रा की अपनी धार्मिक मान्यताए तो है ही, परन्तु यहाँ धार्मिक आध्यात्मिकता के साथ पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए टोलिया यात्रा निकली है ताकि स्वच्छता, जैविक कृषि, हरियाली चुनरी, घाट सफाई नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा, जैविविता, कटाव जैसे विषय के प्रति समाज में जागरूकता लाई जा सके

पंचकोसी यात्रा के पूर्व घाट टोलिया विद्यालय, सामाजिक, धार्मिक संगठन से संपर्क कर यात्रा में सामिल होने का आग्रह करती है यात्रा के समय घाट स्वच्छता, माँ नर्मदा जी की आरती करके यात्रा प्रारंभ की जाती है साथ ही चलते हुए घाटो, खेतो, गाँवो और जंगलो से निकलते समय वहां के स्थानीय जड़ी वुटी कृषि, गाँव के परिवेश और घाटो का अध्ययन करने यात्रा आगे बढ़ती है यात्रा के समय कई स्थानों पर गाँव के लोगो को बैठा कर चौपाल भी की गई साथ ही घाट स्वच्छता के स्लोकन घाटो में चस्पा किये गये इस वर्ष महाकौशल भाग में कुल 10 यात्राए निकली गई जिसमे कुल 232 प्रतिभागियों ने भाग लिया। □



# पर्यावरण पंचकोसी यात्रा - नर्मदापुरम भाग

नर्मदा समग्र, पर्यावरण पंचकोसी यात्रा नर्मदापुरम भाग में आयोजित की गई। नर्मदा समग्र प्रतिवर्ष समाज में विद्यार्थियों, युवाओं, पर्यावरणविद, नर्मदा अनुरागियों के साथ यात्रा को सम्पन्न करता है। यह यात्रा आध्यात्मिक यात्रा के साथ पर्यावरण संरक्षण के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निकाली जाती है। जहां ग्राम चौपाल, विद्यालय में बाल सभा, घाटों और आश्रमों में उपस्थित धर्म प्रेमियों के साथ छोटी-छोटी सभाएं आयोजित कर विषयों को सभी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष नर्मदापुरम में 4 स्थानों में यह पर्यावरण पंच कोसी यात्रा आयोजित की गई जिसमें लगभग 50 पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया। प्रथम यात्रा भारकच्छ कलां से निकाली गई जिसमें 10 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया यह यात्रा 2 दिवसीय और एक रात्रि विश्राम के साथ पूरी की गई यात्रा के मध्य पर्वत पूजन, प्लास्टिक मुक्त घाट, हरियाली चुनरी, रासायनिक खेती जैसे विषयों को लेकर जन जागरण किया गया। यह यात्रा लगभग 7 गांव से होते हुए पूरी हुई। दूसरी यात्रा छिपानेर हरदा जिले से निकाली गई जिसमें 25 महाविद्यालयीन विद्यार्थियों ने भाग लिया यात्रा गोंदागांव से निकाली गई जहां गांजाल नदी और नर्मदा नदी का संगम है। यह यात्रा गोंदागांव से शमसाबाद ग्राम तक निकाली गई मार्ग में आने वाले विद्यालय में विद्यार्थियों से संवाद किया गया तथा बच्चों को ईको ब्रिक्स बनाना और उससे पर्यावरण को क्या लाभ होते की जानकारी दी गई। ऐसी ही यात्रा बुधनी और सीलकंठ में निकाली गई। सभी यात्राओं में लगभग 24 गांवों से संपर्क हुआ जहां पर्यावरण और मां नर्मदा जी के संरक्षण के विषय चर्चा और संवाद स्थापित किया गया। □



# पर्यावरण पंचकोशी यात्रा - मालवा निमाड़ भाग

नर्मदा समग्र भाग मालवा निमाड़ द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पर्यावरण पंचकोशी यात्राओं का आयोजन किया गया भाग मालवा निमाड़ की 9 प्रस्तावित पंचकोशी यात्राओं में से पांच पंचकोशीय यात्राएं पूर्ण हुई इसमें जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी बोरावा एवं प्रियदर्शनी पब्लिक स्कूल बोरावा के छात्र छात्राओं ने सहभागिता की पहली यात्रा जल कोठी (सहस्र धारा) से प्रारंभ होकर

मंडलेश्वर में समापन हुआ दूसरी यात्रा मंडलेश्वर से प्रारंभ हो पथराड जिसका समापन हुआ, तीसरी यात्रा पथराड से शुरू होकर पिटामली तक पहुंची इस प्रकार मां नर्मदा के उत्तर तट पर इन तीन यात्राओं का आयोजन हुआ दक्षिण तट पर मर्कटी संगम माकड़खेड़ा से प्रारंभ हो शालिवाहन मंदिर (नावडातोड़ि) तक यात्रा आयोजित हुई पांचवी यात्रा शालिवाहन वहां से प्रारंभ होकर ढालखेड़ा तक पहुंची यात्रा के दौरान

छात्र-छात्राओं द्वारा मां नर्मदा के किनारे के पर्यावरण को जाना ग्रामीणों से चर्चा की छोटी-छोटी चौपाल के माध्यम से नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन पर सार्थक चर्चा कर एकरिपोर्ट तैयार की गई है।

यात्राओं का क्रमशः समन्वयक नर्मदा समग्र के कार्यकर्ता श्री कमल जी कीर जलकोटी, पवन जी तंवर मंडलेश्वर, गजेंद्र जी पटेल पथराड, श्री नितिन जी डोंगरे माकड़खेड़ा द्वारा किया गया। □



# औषधीय पौधों की पहचान, संरक्षण, संवर्धन एवं गृह वाटिका तैयार करने का प्रशिक्षण

नर्मदा समग्र न्यास द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से जबलपुर, में दिनांक 09-11 अक्टूबर में औषधीय पौधों की पहचान, संरक्षण, संवर्धन एवं औषधीय पौधों की गृह वाटिका तैयार करने के संबंध में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों (9 जिलों) से 30 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हुए (ज्यादातर नर्मदा

जलग्रहण से), जिनमें 24 पुरुष एवं 6 महिलाओं की उपस्थिति रही।

तीन दिवसीय कार्यशाला में औषधीय पौधों की पहचान, उनके बारे में प्रमुख जानकरियाँ, उपयोग, उनके उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, धार्मिक-आध्यात्मिक, पारंपरिक प्रथाएं, सामाजिक, आर्थिक, व्यावहारिक एवं व्यावसायिक विषय बिंदुओं को समाहित करते हुए सत्र आयोजित हुए। जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा न केवल अपना

प्रस्तुतीकरण दिया, अपितु अपने अनुभव साझा करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से चर्चा की एवं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। यह कार्यशाला केवल चर्चात्मक न होकर व्यावहारिक दृष्टिकोण को एवं प्रत्यक्ष रूप में कार्य कैसे हो रहे हैं इसको देखने समझने की दृष्टि से प्रतिभागियों को कृषि विज्ञान केन्द्र, राज्य वन अनुसंधान संस्थान और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का भ्रमण कराया गया। □



नर्मदा समग्र न्यास द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन



“ औषधीय पौधों की पहचान, संरक्षण, संवर्धन एवं गृह वाटिका तैयार करने का प्रशिक्षण ”

9 - 11 अक्टूबर 2023, जबलपुर





# वनों की अग्नि सुरक्षा करने का प्रशिक्षण

नर्मदा समग्र न्यास द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पचमढ़ी जिला नर्मदापुरम में दिनांक 27-29 दिसम्बर में वनों की अग्नि सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण" कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से लगभग 29 प्रशिक्षणार्थी आए हैं (ज्यादातर नर्मदा जलग्रहण से हैं)।

तीन दिवसीय कार्यशाला में वनों की अग्नि सुरक्षा एवं उसके बारे में प्रमुख जानकरियाँ, उपयोग, पारंपरिक प्रथाएं, सामाजिक, आर्थिक, व्यावहारिक विषय बिंदुओं को समाहित



करते हुए सत्र आयोजित हुए। जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा न केवल अपना प्रस्तुतीकरण दिया, अपितु अपने अनुभव साझा करने के साथ ही कार्यकताओं से चर्चा की एवं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। यह

कार्यशाला केवल चर्चात्मक न होकर व्यावहारिक दृष्टिकोण को एवं प्रत्यक्ष रूप में कार्य कैसे हो रहे हैं इसको देखने, करने, समझने की दृष्टि से प्रतिभागियों को मटकुली एवं पचमढ़ी के वन क्षेत्र का भ्रमण भी कराया गया। □

  
**प्रायोजक**

  
**आयोजक**

नर्मदा समग्र न्यास द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

**वनों की अग्नि सुरक्षा**  
**(FOREST FIRE PROTECTION)**  
27-28-29 दिसंबर 2023  
**तीन दिवसीय कार्यशाला**



**स्थान - पचमढ़ी**



स्व. अनिल माधव दवे जन्म जयंती (तिथि अनुसार)  
'विजयादशमी'

'नर्मदा समग्र प्रेरणा दिवस'



# नर्मदा समग्र प्रेरणा दिवस - विभिन्न घाटों व स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों की झलकियाँ



## ‘नदी का घर’ अपने नाम के अनोखेपन से लोगों को आकर्षित करता है

‘नदी का घर’ अपने नाम के अनोखेपन से लोगों को आकर्षित करता है। नदी अनुरागी जो अपरिचित होते हैं वे भी नदी का घर देखकर आकर्षण से खींचे चले आते हैं।

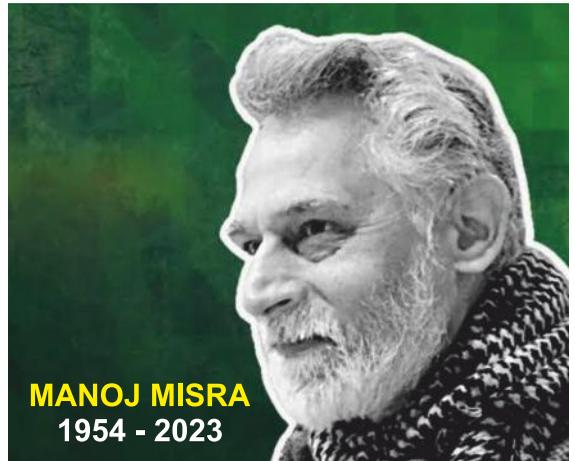
ऐसी ही घटना आज घटी। अचानक एक अपरिचित गरिमामयी महिला और सुपुष्ट पुरुष, नदी का घर नाम देख कर मिलने आ गये। महिला नदियों पर विशद कार्य करने वाले

स्वर्गीय मनोज मिश्रा जी की बहन थीं और उनके साथ में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. बक्शी, उनके परिजन भी थे। साथ ही स्व. मनोज मिश्रा जी की माता जी जो की अब तक कार में बैठी थी, उन्हें भी बुलालिया गया।

नदी ने अपरिचय के सभी सेतु ढहा दिये। नदी से अनुराग रखने वाले, नदियों पर चिंता करने वाले और नदियों से जुड़े लोग जब मिलते हैं तो ऐसा लगता

है जैसे कि समान धर्मी साथ हों।

उन्हें ‘नदी का घर’ से एवं ‘नर्मदा समग्र’ के कार्यों व गतिविधियों से अवगत कराया, साथ ही प्रकाशित सामयिक पत्रिका, अन्य प्रकाशित सामग्री और स्व. अनिल माधव दवे जी द्वारा लिखित पुस्तकें ‘सृजन से विसर्जन तक’ एवं शिवाजी महाराज के सुशासन पर केंद्रित ‘शिवाजी & सुराज’ पुस्तक भेंट की। □



# नर्मदा समग्र न्यास और रेडक्रॉस सोसाइटी म.प्र. के सहयोग से आयोजित हायजिन कीट वितरण कार्यक्रम

चतुर्थ चरण - 05 अक्टूबर 2023

नदी एम्बुलेंस कार्यक्षेत्र के ग्राम झण्डाना, तह. सोंडवा, जि. अलीराजपुर में आज (05/10/23) रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा प्रदत्त हाइजेनिक किट का 83 महिलाओं को वितरण किया गया। अतिथि के रूप में सोंडवा जनपद सदस्य श्रीमति झेण्डली सोलिया, गांव के पटेल श्री रुमालिया सस्तिया, ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमति रमीला सस्तिया, ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेमसिंह चमेलका, सहायक सचिव भूरसिंह सस्तिया उपस्थित रहे। साथ ही नदी एम्बुलेंस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। □



# हायजिन कीट वितरण एवं टीकाकरण कार्यक्रम

पंचम चरण - 22 दिसम्बर 2023

नदी एम्बुलेंस कार्यक्षेत्र के ग्राम कोटबांधनी एवं भादल, तहसील पाटी, जिला बड़वानी में दिनांक 22.12.2023 रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा प्रदत्त हाइजेनिक किट का 163 महिलाओं को वितरण किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग बड़वानी की टीम द्वारा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।

अतिथि के रूप में बड़वानी जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलवंत पटेल, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. चंद्रजीत सांवले, जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनकी टीम, नर्मदा समग्र के मुख्य समन्वयक श्री मनोज जोशी, भाग टोली सदस्य श्री मिथुन यादव, कार्यकर्ता श्री नितिन डोंगरे उपस्थित रहे। साथ ही नदी एम्बुलेंस का स्टाफ भी मौजूद रहा।

18 मई 2023 नर्मदा समग्र प्रेरणा दिवस से आरंभ हुए किट वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई किटों में से शेष हायजिन किट का वितरण कर यह इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम रहा। शीघ्र ही रेड क्रॉस से आगामी वर्ष हेतु किट उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है, जिससे नदी एम्बुलेंस कार्यक्षेत्र के शेष ग्रामों में भी किट वितरित की जा सके। □





नदी उत्सव की स्मारिका श्री प्रल्हाद पटेल जी को Mpcst Bhopal के महानिदेशक डॉ. डॉ अनिल कोठारी जी, नर्मदा समग्र के श्री करण सिंह कौशिक जी एवं कार्तिक सप्रे जी ने भेंट की।



वन पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति कल्याण मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री नागर सिंह चौहान 31 दिसंबर २०२३ को अपने ककराना प्रवास के दौरान नर्मदा समग्र के प्रकल्प रेवा सेवा केंद्र पधारें एवं संस्था की गतिविधियों विशेष कर नदी एम्बुलेंस के बारे में जाना। केंद्र के अवलोकन उपरांत उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा भी की एवं सभी अपने क्षेत्र के विकास में सहभागी होने और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों से जुड़ने और सहयोग करने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर नर्मदा समग्र मुख्य समन्वयक, भाग टोली सदस्य, स्थानीय कार्यकर्ता एवं केंद्र व नदी एम्बुलेंस का स्टाफ के सदस्य भी उपस्थित रहे।

नर्मदा सहित समस्त नदियों पर एकाग्र कार्य करने हेतु "नर्मदा समग्र" एक सुप्रतिष्ठित एवं समादृत संस्था है जिसे स्व. अनिल माधव दवे एवं स्व. अमृतलाल वेगड़ का मणि कांचन नेतृत्व प्राप्त रहा है। नर्मदा समग्र को मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का पर्यावरण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार "मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" प्राप्त है।

नर्मदा जी में जल बढ़े और प्रदूषण घटे, इन दो आयामों पर केन्द्रित गतिविधियां संचालित होती है। नर्मदा समग्र जमीनी स्तर पर विभिन्न मंचों, गतिविधियों के माध्यम से नर्मदा जी के जलग्रहण क्षेत्र व पर्यावरण के सम्बन्ध में जागरूकता निर्माण का काम करता है।

इन्हीं गतिविधियों को आगे बढ़ाने विशेषकर पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली, प्राकृतिक कृषि, नदी पारिस्थितिकी तंत्र, नर्मदा किनारे का समाज और संस्कृति इत्यादि विषयों को जन-जन तक ले जाने, जागरूकता बढ़ाने और नदी संरक्षण एवं स्वस्थ जलग्रहण के लिए सहभागिता बढ़ाने हेतु नर्मदा समग्र का सामुदायिक रेडियो स्टेशन (Community Radio Station) "रेडियो रेवा" का जबलपुर में प्रसारण प्रारंभ हो चुका है। विगत 15 वर्षों से नर्मदा समग्र द्वारा नर्मदा जी के स्वस्थ जलग्रहण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और नदी के विभिन्न पहलुओं को नये स्वरूप में 'रेवा रेडियो' के माध्यम से समाज के बीच लाने की यह एक पहल है।

रेवा रेडियो के माध्यम से नर्मदा किनारे का समाज और संस्कृति को केंद्र में रख कर और स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु जान जागरूकता एवं जन सहभागिता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रम आयोजित एवं प्रसारित किए जाएँगे। विभिन्न चरणों में नर्मदा किनारे बसे समुदायों को चिन्हित कर व्यक्तिगत व सामूहिक चर्चाओं के माध्यम से स्थानीय लोक परम्पराओं, जैव विविधता, गीत-संगीत, कृषि देशज, खाद्यान्न व जल संरक्षण की परम्पराओं को संकलित करना। विशिष्ट स्थलों के इतिहास व उनसे जुड़ी विभिन्न कथा/कहानियों व तथ्यों को एकत्रित करना एवं संगोष्ठियों, सम्मेलनों, यात्राओं के माध्यम से नर्मदा संरक्षण व देशज ज्ञान के प्रति वातावरण निर्माण करना। इन कार्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति की सेवा में जुटे व्यक्तियों/संस्थाओं से संवाद, नर्मदा नदी के किनारों पर होने वाली गतिविधियों के समाचार और बच्चों, युवाओं, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए भी कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे।

### सामुदायिक रेडियो केंद्र, "रेवा रेडियो" के मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य रहेंगे -

- ▶▶ नदी-पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, जीवनशैली, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर जागरूकता एवं जन-भागीदारी बढ़ाना;
- ▶▶ नर्मदा किनारे की लोक कलाओं का दस्तावेजीकरण और उन्हें आमजन से अवगत करवाना;
- ▶▶ बच्चों एवं किशोर-किशोरियों के लिए story telling के माध्यम से लोक कलाओं को उजागर करना;
- ▶▶ युवाओं को नर्मदा संरक्षण हेतु प्रेरित करना व विविध नवाचारों से जोड़ते हुए नर्मदा के प्रति समग्र दृष्टिकोण विकसित करना;
- ▶▶ नर्मदा के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास एवं लोक कलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक पक्ष पर विशेषज्ञों से चर्चा;
- ▶▶ समय-समय पर विभिन्न विधाओं के कलाकारों को कार्यक्रमों के माध्यम से मंच प्रदान करना;
- ▶▶ शासकीय लाभप्रद योजनाओं की जानकारी सामान्य जनता तक पहुंचाना।

### सामुदायिक रेडियो स्टेशन की विशेषताएँ-

- ▶▶ स्थानीय सूचना का माध्यम एवं कई स्थान पर विशेष कर ग्रामीण अंचलों में प्रिंट मीडिया के मुकाबले रेडियो ज्यादा सुना जाता है;
- ▶▶ लोगों को संवाद करने और अपनी आवाज में बात रखने का मौका मिलता है, संवाद कार्यक्रमों से अथवा किन्हीं विशेष मुद्दों पर विषय विशेषज्ञों की राय अधिकतम लोगों तक, कम समय में पहुंचायी जा सकती है;
- ▶▶ सरकार की सूचनाओं और योजनाओं को जन-सामान्य तक पहुंचाने के सुलभ माध्यम।

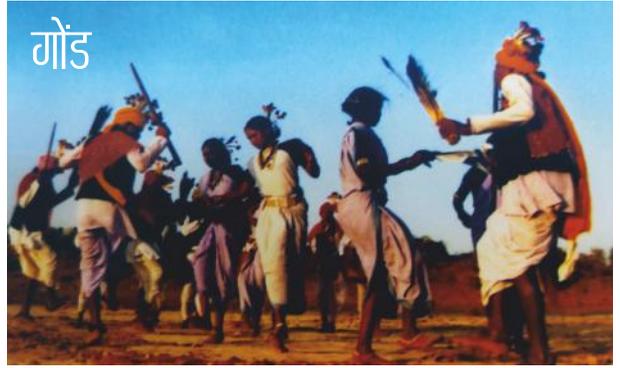


**रेडियो रेवा**

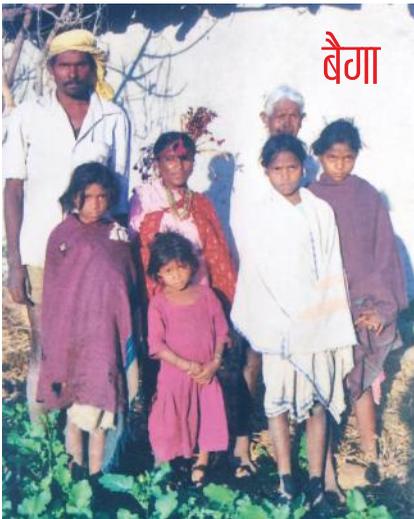
'उद्योग भवन', पाँचवीं मंजिल  
एम.सी.आई. कॉलोनी, कटंगा, जबलपुर, म.प्र. - 482001  
दूरभाष : + 91 761 2998544  
ईमेल - radiorewa90.8@gmail.com



गोंड म.प्र. की सबसे बड़ी जनजाति है। सतपुड़ा और मैकल की वादियों में वे निवास करते हैं। अमरकंटक से लेकर खंडवा, बुरहानपुर तक म.प्र. के विभिन्न जिलों में यह जाति पाई जाती है। गोंडवाना राज्य का बड़ा समृद्ध इतिहास है। मध्यम कद के सुगठित शरीर वाले, आभूषण प्रिय, नर्मदा से विशेष प्रेम करने वाला यह समाज गोंडी भाषा बोलता है। इनके आराध्य देव बड़ा देव हैं। पर्व-त्योहारों व नृत्य-संगीत में इनकी गहरी रुचि है व समृद्ध परंपराएँ हैं।



नर्मदा तट पर नृत्य करते गोंड नर-नारी



बैगा परिवार

## कोरकू

कोरकू वनवासी सतपुड़ा के वनों में विशेषकर बैतूल, होशंगाबाद व खंडवा में निवासरत हैं। रूपा, पोतड़िया, दुलरिया एवं बोवई इनके चार समूह हैं एवं 36 गौत्र हैं। कोरकू सरल व परिश्रमी होते हैं। उन्हें आभूषण प्रिय हैं। उनके जीवन में विभिन्न संस्कारों की प्रधानता है। संस्कार के समय गायन की समृद्ध परंपरा है। ये मुण्डा भाषी व संगीत प्रेमी हैं।



ताल और तरेंग में तन्मय एक वनवासी

म.प्र. के पूर्वी भाग में नर्मदा तट पर निवासरत इस अति प्राचीन वनवासी समाज में मरावी, धुर्वे, मरकाम, परते, तेकाम आदि गौत्र हैं। इनकी 108 उपजातियाँ हैं। ये शिकार प्रेमी, भोजन में कोदों, कुटकी, मक्का व मांसाहार पसंद करते हैं। कृषि, पशुपालन इनके प्रमुख व्यवसाय हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक इनमें संस्कारों की परंपरा है। इनके आराध्य ठाकुर देव, बड़े देव हैं। बिदरी, हरेली, दशहरा, दिवाली, छेत्रा जैसे त्योहार मनाते हैं। भित्ति चित्रों में नोह-डोरा व पक्षियों की आकृतियों को विशेष तरह से उकेरने में इन्हें महारत प्राप्त है। वन औषधियों का इनका ज्ञान विश्व की किसी भी जनजाति से अधिक होगा। बैगा ही ऐसा समाज है जो एक ही वर्ष में किसी पेड़ अथवा पौधे को साल में छह माह एक नाम से व दूसरे छह माह अलग नाम से बुलाता है। उनकी मान्यता है कि मौसम के अनुसार वृक्ष अपनी तासीर बदलता है।

## बारैला

बारैला निमाड़ व खानदेश में बहुतायत निवास करते हैं। इनकी बहुत कुछ परम्पराएँ भीलों के समान हैं। समाज की संरचना कुल, समूह, गौत्र, युग्म संगठन पर आधारित है। इसकी विशिष्ट पारिवारिक संरचना है। अपनी प्रथाओं में वे टोडगा, घामा, गोद, घर जमाई, घूँघट जैसी प्रथाओं को मानते हैं। खालूनदेव, बगासा, कुवर देव, कसूमर जैसे देवों की पूजा करते हैं। पिठौरा चित्रण व पशु पक्षियों की मूर्तियाँ बनाने में इन्हें दक्षता हासिल है। इंदल, पोला, डोंडर, अमावस, दशहरा, मवेशी उत्सव, खेतरपाल पूजा, दिवाली, भगौरिया, होली जैसे विभिन्न उत्सवों को मनाते हैं। गीत-संगीत व शिल्प इनकी विशेषता है।

(साभार - नर्मदा समग्र Rafting through a civilisation A TRAVELOGUE)

“जहन् घुल रहा नभ, जल, धल में  
जहन् अन्न, सब्जी, फल में  
सोचो क्या रवार्ये, क्या न रवार्ये  
जहरो से कैसे जान बचार्ये...”



नेचरल फाउंडेशन

नर्मदा जल ग्रहण को रसायन मुक्त करने की पहल

स्वस्थ परिवार - स्वस्थ भूमि  
स्वस्थ नर्मदा मैया



# पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं

## Eco System Services



नर्मदा समग्र द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष, फरवरी 2024 में कार्यशाला का आयोजन अलीराजपुर जिले में पदस्थ राज्य सेवा के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए किया जायेगा।



स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्री करण सिंह कौशिक द्वारा नियो प्रिंटरर्स, 17 बी-सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल एवं नदी का घर  
सीनियर एम.आई.जी.-२ अंकुर कॉलोनी, पारुल अस्पताल के पास शिवाजी नगर, भोपाल-46१016 से प्रकाशित।  
संपादक कार्तिक सप्रे। फोन नं. : 0755-१460754